PRGI Reg. No. : CTHIN/25/A1911

हिन्दी दैनिक

लोकतंत्र प्रहरी

● वर्ष-01 ● अंक- 307 ● भिलाई, शुक्रवार 19 जून 2026 ● हिन्दी दैनिक ● पृष्ठ संख्या-8 ● मूल्य - 2 रुपया ● संपादक- संजय तिवारी, मो. 9200000214

संक्षिप्त समाचार

नक्सलियों के छिपाए हथियारों का जखीरा बरामद, बीएसएफ को बड़ी सफलता

नारायणपुर। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के मसपुर-गुडरापाल जंगल क्षेत्र में चलाए गए सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीएसएफ की 133वीं वाहिनी ने जंगल में छिपाकर रखे गए हथियारों, गोला-बारूद और अन्य सामग्रियों का डंप बरामद किया है। जानकारी के अनुसार 16 जून को बीएसएफ की 133वीं वाहिनी की 'ई' कंपनी द्वारा कैंप मसपुर से आसपास के वन क्षेत्रों में विशेष सर्च अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान जवानों को जंगल के भीतर एक संदिग्ध स्थान दिखाई दिया। क्षेत्र की घेराबंदी कर तलाशी लेने पर वहां छिपाकर रखा गया हथियारों और अन्य सामग्रियों का जखीरा मिला। बरामद सामग्री में एक देसी बीजीएल लॉन्चर, सात बीजीएल गन, एक 12 बोर राइफल, 37 राउंड कारतूस, 15 मीटर वायर तथा पांच पोच शामिल हैं। सुरक्षा बलों ने सभी सामग्रियों को जब्त कर लिया है। प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि उक्त हथियार और अन्य सामग्री पहले से जंगल में छिपाकर रखी गई थी, जिसका उपयोग नक्सली गतिविधियों में किया जाना था। सुरक्षा बलों की सतर्कता और लगातार चलाए जा रहे अभियान के चलते इस डंप का पता लगाया जा सका।

मोदी 19 जून को विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2,400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि करेंगे जारी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून (शुक्रवार) को आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएम-वीबीआरवाई) के तहत लगभग 2,400 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि जारी करेंगे। इसकी घोषणा बुधवार को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से की गई। पीएमओ के अनुसार, योजना की शुरुआत के बाद से अब तक देशभर में लगभग 15 लाख रोजगार अवसरों के सृजन में सहायता मिली है। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

ट्रंप और पेजेश्कियान ने खत्म की महीनों पुरानी जंग

अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर लगी मुहर...

नई दिल्ली/ एजेंसी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी नेतृत्व के बीच मध्य पूर्व में जारी सैन्य संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से 14 सूत्रीय समझौता संपन्न हुआ है। अमेरिकी अधिकारियों द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस द्विपक्षीय समझौते का मुख्य उद्देश्य वैश्विक ऊर्जा बाजार को स्थिर करना और व्यापारिक मार्गों को बहाल करना है। अमेरिका ईरान और इस युद्ध में शामिल उनके साथी देश, इस समझौते पर दस्तखत करके लेबनान सहित सभी मोर्चों पर लड़ाई और सैन्य कार्यवाहियों को तुरंत और हमेशा के लिए रोकने का ऐलान करते हैं। वे वादा करते हैं कि अब से वे एक-दूसरे के खिलाफ कोई युद्ध या हमला शुरू नहीं करेंगे, न ही एक-दूसरे को डराएंगे या ताकत का इस्तेमाल करेंगे। वे लेबनान की सीमाओं और उसकी आज़ादी की रक्षा करेंगे। आखिरी समझौते में भी इन सभी बातों की पक्की पुष्टि की जाएगी। अमेरिका और ईरान एक-दूसरे की आज़ादी और सीमाओं का सम्मान करने और एक-दूसरे के घरेलू या अंदरूनी मामलों में दखल न देने का वादा करते हैं। अमेरिका और ईरान आपस में बातचीत करके ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिनों के भीतर आखिरी फैसला करने का वादा करते हैं। अगर दोनों देश चाहें, तो इस समय को आगे भी बढ़ा सकते हैं। इस समझौते पर दस्तखत होते ही, अमेरिका ईरान के खिलाफ की गई अपनी समुद्री घेराबंदी और रास्ते की रुकावटों को हटाना शुरू कर देगा, और 30 दिनों के

भीतर इस घेराबंदी को पूरी तरह खत्म कर देगा। इस दौरान, जहाजों का आना-जाना उसी रफ्तार से शुरू होगा जैसा युद्ध से पहले था। इसके अलावा, अमेरिका आखिरी समझौता होने के 30 दिनों के भीतर ईरान के आस-पास के इलाकों से अपनी सेनाएं भी हटा लेगा। इस समझौते पर दस्तखत होते ही, ईरान अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि व्यापारिक जहाज बिना किसी टैक्स के 60 दिनों तक फारस की खाड़ी से ओमान सागर तक सुरक्षित आ-जा सकें। व्यापारिक जहाजों का आना-जाना तुरंत शुरू होगा। तकनीकी और सैन्य रुकावटों को हटाने व समुद्री बारूदी सुरंगों को साफ करने के लिए ईरान को जो समय चाहिए, उसे देखते हुए इसे 30 दिनों के भीतर पूरी तरह चालू कर दिया जाएगा। ईरान, अंतरराष्ट्रीय कानूनों को ध्यान में रखते हुए, होर्मुज जलडमरूमध्य के भविष्य के इंतजामों और समुद्री सेवाओं को तय करने के लिए ओमान और खाड़ी के अन्य पड़ोसी देशों के साथ बातचीत करेगा। अमेरिका अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर ईरान को दोबारा बसाने और उसकी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कम से कम 300 अरब डॉलर की एक पक्की योजना बनाएगा। इस योजना को कैसे लागू किया जाएगा, इसका तरीका 60 दिनों के भीतर आखिरी समझौते में तय होगा।

वर्साय के ऐतिहासिक महल में लगी मुहर...

इस समझौते का महत्वपूर्ण पल फ्रांस के पैलेस ऑफवर्सैलिस में देखने को मिला। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वहां फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ डिनर पर मौजूद थे। इसी दौरान ट्रंप ने समझौते की हार्ड कॉपी पर अपने हस्ताक्षर किए और पत्रकारों के सामने गर्व से चिल्लाते हुए कहा 'Its signed'। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, यह समझौता तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और इसकी डिजिटल प्रतियां तुरंत ईरान और मध्यस्थता कर रहे देशों को भेज दी गई हैं। इस समझौते की सबसे अहम शर्त यह है कि अगले 60 दिनों तक दोनों देशों को पूर्ण संयम बरतना होगा। इस अवधि के दौरान अमेरिका और ईरान दोनों ही किसी भी ऐसे सैन्य, आर्थिक या राजनीतिक कदम से बचेंगे, जिससे आपसी विश्वास को ठेस पहुंचे या समझौते के क्रियान्वयन में बाधा आए।

पुलिस ने 4 करोड़ रुपये किए फ्रीज

पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे के साथ 7.8 करोड़ की ऑनलाइन ठगी

नई दिल्ली/ एजेंसी

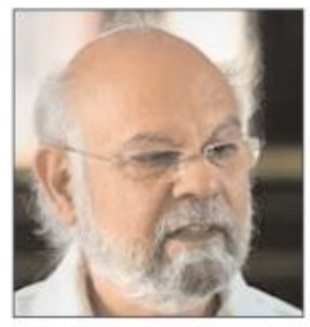

पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के बेटे और पूर्व सांसद नरेश कुमार गुजराल एक बड़े साइबर फ्रॉड का शिकार हो गए हैं। ठगों ने उनकी तस्वीर का इस्तेमाल कर व्हाट्सएप पर फर्जी प्रोफाइल बनाई और उनके एक भरोसेमंद कर्मचारी को मैसेज भेजकर करीब 7.8 करोड़ रुपये अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करा लिए। मामले में दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और ई-एफआईआर दर्ज की गई है।पुलिस के अनुसार, साइबर अपराधियों ने नरेश गुजराल के नाम से उनके फाइनेंस विभाग के एक कर्मचारी से संपर्क किया। खुद को नरेश गुजराल बताते हुए ठग ने कहा कि वह एक महत्वपूर्ण बैठक में व्यस्त हैं और तत्काल कुछ भुगतान करने हैं। कर्मचारी ने निर्देशों को सही मानते हुए 12 से 16 जून के बीच चार अलग-अलग आरटीजीएस ट्रांजैक्शन किए। इन लेनदेन के जरिए कुल 7.8 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए गए।मामले का खुलासा तब हुआ जब कर्मचारी ने इन ट्रांजैक्शनों की जानकारी नरेश गुजराल की बेटी दीक्षा को दी। दीक्षा ने इसकी पुष्टि के लिए अपने पिता से संपर्क किया। नरेश गुजराल ने साफ किया कि उन्होंने किसी भी तरह के भुगतान का निर्देश नहीं दिया था। इसके बाद परिवार को साइबर ठगी का एहसास हुआ।फ्रॉड का पता चलते ही दीक्षा ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई और ई-एफआईआर करवाई।

पिनाराई की बेटी वीणा मंथली पेमेंट केस में पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष पेश हुई

कोच्चि। विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन की बेटी वीणा टी, मंथली पेमेंट केस के सिलसिले में पूछताछ के लिए कोच्चि में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफिस में पेश हुईं. अपने पति और पूर्व मंत्री पी ए मोहम्मद रियास के साथ वह सुबह करीब 10:30 बजे कड़ी सुरक्षा वाले एजेंसी ऑफिस पहुंचीं. यह केंद्रीय एजेंसी द्वारा जारी किया गया दूसरा नोटिस है जिसमें वीना को पूछताछ के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है. जब एक सप्ताह पहले शुरुआती समन भेजा गया था, तो उन्होंने स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए दो सप्ताह की मोहलत मांगी थी. हालाँकि, जांच टीम ने केवल पांच दिन की मोहलत दी।

हाई कोर्ट ने स्पीकर के फैसले पर नहीं लगाई रोक

ऋतब्रत बनर्जी ही रहेंगे पश्चिम बंगाल में विपक्ष दल के नेता

नई दिल्ली/ एजेंसी

पश्चिम बंगाल की राजनीति में चल रहे सत्ता संघर्ष के बीच ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाई कोर्ट से एक बड़ा कानूनी और राजनीतिक झटका लगा है। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता के पद को लेकर छिड़े विवाद में कोर्ट ने फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) के फैसले में हस्तक्षेप करने या उस पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। जस्टिस कृष्णा राव की पीठ ने स्पष्ट किया कि इस मामले में अंतरिम आदेश देने के लिए कोई प्रथम दृष्टया आधार नहीं मिला है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष रथिन बसु ने ऋतब्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त कर दिया। इस फैसले को चुनौती देते हुए तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले शोवनदेव चट्टोपाध्याय ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि स्पीकर के इस आदेश पर तुरंत अंतरिम रोक लगाई जाए।बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस कृष्णा राव ने स्पीकर की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने एडिशनल एडवोकेट जनरल से पूछा कि आखिर 9 मई को मिले उस पत्र पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जिसमें शोवनदेव चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता बनाने का प्रस्ताव दिया गया था? कोर्ट ने गौर किया कि जहां पहले पत्र को नजरअंदाज किया गया, वहीं बागी गुट द्वारा 3 जून को दिए गए।

स्ट्रीट फाइटर के अवतार में दिखीं ममता

अब ड्रोन शॉट दिखाने की हिम्मत नहीं-ममता

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में सत्ता गंवाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को एक बार फिर सड़कों पर स्ट्रीट फाइटर वाले अवतार में नजर आईं। पार्टी में टूट और लगातार पुराने मामलों में कानूनी जांच के बीच ममता धरमतला में हॉकरों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुईं। हॉकरों का यह प्रदर्शन अवैध बेदखली के खिलाफ था। विरोध प्रदर्शन के समर्थन में टीएमसी भी सड़कों पर उतरी। इसकी जानकारी टीएमसी के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर साझा की गई। पार्टी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर इस प्रदर्शन को साझा करते हुए लिखा, हमारी चेयरपर्सन ममता बनर्जी ने पार्टी नेताओं और समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, पूरे बंगाल में हॉकरों को गैर-कानूनी, अन्यायपूर्ण और बेहद अमानवीय तरीके से हटाए जाने के खिलाफ एक शांतिपूर्ण विरोध मार्च का नेतृत्व किया। पार्टी ने लिखा, बंगाल के लोग हमेशा सबसे पहले रहे हैं। उनके सम्मान, आजीविका और अधिकारों की रक्षा अटूट संकल्प के साथ की जाएगी, और इस लड़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सिर्फ सत्ता के लालच और आम नागरिकों की पूरी तरह अनदेखी करने वाली बेरहम भाजपा सरकार जल्द ही अपनी ही जन-विरोधी नीतियों के बोझ तले गिर जाएगी।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुरू हुआ कार्गो ऑपरेशन, व्यापार और लॉजिस्टिक्स को मिलेगी रफ्तार

नई दिल्ली। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने आज अपनी पहली कार्गो फ्लाइट संभालकर एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। यह कार्गो विमान घरेलू रूट पर संचालित हुआ। कुछ दिन पहले ही एयरपोर्ट ने व्यावसायिक यात्री उड़ानों की शुरुआत की थी। अब कार्गो सेवाएं शुरू होने के बाद यह परियोजना उत्तर भारत के एक बड़े विमानन और लॉजिस्टिक्स केंद्र के रूप में तेजी से आगे बढ़ रही है। इससे क्षेत्र में व्यापार और माल परिवहन को नई गति मिलने की उम्मीद है।

देश में मॉनसून संकट गहराया

42 प्रतिशत कम बारिश,जून सूखा पड़ा रहा,अब जुलाई में भी रिकवरी मुश्किल

नई दिल्ली। भारत में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की रफ्तार धीमी बनी हुई है। लगातार तीसरे साल जून में मानसून ने लंबा ब्रेक लिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, 4 जून से 18 जून के बीच बारिश की कमी बढ़कर 42 प्रतिशत हो गई है। इस दौरान देश में सामान्य 72.2 प्रतिशत बारिश के मुकाबले सिर्फ 42.1प्रतिशत बारिश हुई, जो मॉनसून शुरू होने के बमुश्किल दो हफ्ते बाद ही इस मौसम के सामने बढ़ती चुनौती को दिखाता है। ज़िलेवार बारिश का ताजा मैप चिंताजनक तस्वीर पेश

करता है। मध्य, पूर्वी और प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्से बारिश की कमी (-20 प्रतिशत से -59 प्रतिशत) या बहुत ज्यादा कमी (-60 प्रतिशत से -90 प्रतिशत) वाली कैटेगरी में आते हैं। सिर्फ उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ इलाकों और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में ही जरूरत से ज्यादा बारिश हुई है। 18 जून को INSAT-xDS से मिली सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि हालात का सामान्य होना मुश्किल क्यों बना हुआ है। तस्वीर में पश्चिमी हिमालय और उससे सटे उत्तरी इलाकों में बादलों का घना जमावड़ा दिख रहा है, जो एक सक्रिय 'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' (पश्चिमी विक्षोभ) से जुड़ा है। वहीं, मध्य भारत, महाराष्ट्र, गुजरात और मॉनसून के मुख्य क्षेत्र का ज्यादातर हिस्सा काफी हद तक बादलों से मुक्त है। अरब सागर वाली शाखा कमजोर लग रही है और पश्चिमी तट पर गहरे संवहन की गतिविधि सीमित है, जबकि बंगाल की खाड़ी वाली शाखा पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में कहीं-कहीं तूफानी बादलों के समूह बना रही है।

मुंबई नगर निगम को पूरी तरह से ध्वस्त करने की तैयारी

ठाकरे गुट में होगी एक और टूट-6 सांसदों के बाद 20 पार्षद ऑपरेशन टाइगर के अगले चरण पर शिंदे गुट का बड़ा इशारा

नई दिल्ली/ एजेंसी

महाराष्ट्र की सियासत में 'ऑपरेशन टाइगर' के जरिए लोकसभा के 6 सांसदों को अपने पाले में करने के बाद, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने अब उद्धव ठाकरे के सबसे मजबूत और ऐतिहासिक गढ़ यानी मुंबई नगर निगम को पूरी तरह से ध्वस्त करने की तैयारी कर ली है। दिल्ली में सांसदों की बगावत की औपचारिकताएं पूरी होने के ठीक बाद, शिंदे गुट के पूर्व पार्षद और वरिष्ठ नेता किरण लांडगे ने एक बेहद सनसनीखेज दावा किया है। लांडगे के मुताबिक, उद्धव ठाकरे गुट के 20 से अधिक मौजूदा और पूर्व पार्षद इस समय शिंदे समूह के शीर्ष नेतृत्व के सीधे संपर्क में हैं और जल्द ही पाला बदलने वाले हैं। इस बड़े खुलासे के बाद देश के सबसे अमीर नगर निगम (बीएमसी) और मुंबई की स्थानीय राजनीति में एक नया और जबरदस्त भूचाल आना तय माना जा रहा है। लांडगे के दावे के बाद से शिवसेना यूबीटी के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराते दिख रहे हैं। शिंदे गुट के नेता किरण लांडगे ने मीडिया से

बातचीत में जमीनी स्तर पर चल रही राजनीतिक हलचलों को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, ठाकरे की शिवसेना के कई महत्वपूर्ण पार्षद हमारे काम और विचारधारा से प्रभावित होकर हमारे संपर्क में हैं। वर्तमान में 20 से अधिक ऐसे पार्षद हैं जो बहुत जल्द शिंदे समूह में शामिल होने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं और उनकी बातचीत अंतिम चरण में है। गौरतलब है कि मुंबई नगर निगम में ठाकरे समूह के कुल 65 पार्षद हैं। यदि किरण लांडगे का यह दावा सच साबित होता है और 20 से अधिक पार्षद बगावत करते हैं, तो बीएमसी पर पिछले तीन दशकों से चला आ रहा ठाकरे परिवार का एकाधिकार और राजनीतिक ताकत पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। साल 2022 में महाविकास अघाड़ी सरकार गिरने और शिवसेना में हुए ऐतिहासिक विभाजन के बाद से ही दोनों गुटों के बीच विधायकों, सांसदों और स्थानीय पदाधिकारियों को अपनी ओर खींचने की रस्साकशी लगातार जारी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सांसदों के सफल दलबदल के बाद अब 'ऑपरेशन टाइगर' के अगले चरण के तहत मुंबई, ठाणे और कल्याण-डोंबिवली नगर निगमों के बचे हुए ठाकरे समर्थकों को निशाना बनाया जा रहा है। किरण लांडगे के इस बयान ने उन चर्चाओं को और भी मजबूत कर दिया है कि आगामी बीएमसी चुनावों की घोषणा से पहले महायुति (बीजेपी-शिंदे-अजित पवार) ठाकरे गुट को पूरी तरह से पंगु बना देना चाहती है।

ममता को बिरला ने दिया बड़ा मौका

अभिषेक को अपना पक्ष रखने भेजा बुलावा.....

नई दिल्ली। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को बैठक के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुलाया है. टीएमसी में चल रही गुटबाजी के बीच टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सामने पेश हों और अपना पक्ष रखें. लोकसभा अध्यक्ष ने इसके लिए अभिषेक बनर्जी को 19 जून को मिलने के लिए समय दिया है. स्पीकर ओम बिरला सांसदों के विलय और पार्टी के पदों से जुड़े मामले पर दोनों पक्षों की बात सुनना चाहते हैं. अभिषेक बनर्जी को शुक्रवार, 19 जून को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया है. यह घटनाक्रम विधानसभा चुनावों के बाद टीएमसी के भीतर बढ़ते मतभेदों के बीच सामने आया है. सूत्रों ने बुधवार को बताया कि ओम बिरला ने 20 बागी सांसदों और इस मामले पर उनके रुख पर चर्चा करने के लिए अभिषेक बनर्जी को 19 जून को बुलाया है.

18 माह से मनरेगा में सन्नाटा, पुल-पुलिया और चेकडैम के लिए तरस रहीं पंचायतें

गरियाबंद। देवभोग जनपद पंचायत क्षेत्र में विकास कार्यों की रफ्तार पर मानो ब्रेक लग गया है। हालत यह है कि पिछले 18 महीनों में मनरेगा के तहत एक भी पुल, पुलिया, चेकडैम या बड़ा निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं हो पाया है ग्रामीण विकास की रीढ़ मानी जाने वाली इस योजना में लंबे समय से नई स्वीकृतियां नहीं मिलने के कारण पंचायतें बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रही हैं वो तो भला हो कांग्रेस विधायक निधि और मध्य आदिवासी विकास प्राधिकरण समग्र योजना का जिसके चलते कुछ पंचायतों में विकास की झलक देखने को मिल रहा है अगर विधायक मद की बात करे तो बीते सत्र करीब 25 पुल सड़क दिया रहा साथ ही इस सत्र में पाँच पंचायतों में पानी टंकी दिया गया इसके अलावा केंटपदर माहुलकोट खुटगांव बरकानी कुमड़ाई खुर्द गोहेकेला निष्ठिगुड़ा में समग्र योजना के तहत बीते सत्र में सड़क और शेड स्वीकृत रहा साथ ही मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के तहत पिछले साल 5 पंचायत और इस

बार 8 पंचायत में सड़क स्वीकृत किया गया है एवं राज्यसभा संसद के अनुसार पर लाटापारा में पुलिया स्वीकृति दिया गया साथ ही महासमुंद लोकसभा सांसद द्वारा देवभोग पर सरस्वती शिशु मंदिर भवन के लिए 10, लाख दिया तब कहीं जाकर गिनते के पंचायत हल्की विकास दिखी लेकिन नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को करीब करीब महीना होने को है मगर अब तक मनरेगा से एक पंचायत में ना पुल मिला न चेकडैम ऐसे में जो सरपंच थोड़ी बहुत आर्थिक तौर पर सक्षम है वह जोड़ तोड़ कर पंचायत में विकास की हल्की फुल्की झलक दिखा पा रहे हैं लेकिन जिनकी हालत पतली है वह मनरेगा की ओर मुंह ताके बैठे है इस बीच कई सरपंचों का कहना है कि गांवों में ऐसे अनेक स्थान हैं जहां बरसों से पुल-पुलिया और चेकडैम की आवश्यकता है बरसात के दिनों में ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी होती है, लेकिन पंचायतें चाहकर भी निर्माण कार्य नहीं करा पा रही हैं कारण साफ है मनरेगा से स्वीकृति नहीं मिल रही इसके अलावा सरपंचों ने सवाल उठाया है कि यदि मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आधारभूत ढांचा विकसित करना है तो फिर देवभोग क्षेत्र को इससे वंचित क्यों रखा जा रहा है आखिर 18 महीनों से विकास कार्यों पर लगी इस अदृश्य रोक का जिम्मेदार कौन है दुर्भाग्य की बात तो यह है कि गिने चुने ब्लॉक के कुछ तालाबो में पचरी दिया है लेकिन यह संख्या जरूरत के मुकाबले बेहद कम है इसके साथ जनपद सदस्यों का भी कहना है कि विकास कार्यों के लिए पंचायतों को दूसरी योजनाओं की ओर देखना पड़ रहा है, जबकि मनरेगा जैसी बड़ी योजना लगभग निष्क्रिय नजर आ रही है। जनपद पंचायत के इतिहास में शायद यह पहला अवसर है जब इतनी लंबी अवधि तक पुल-पुलिया और चेकडैम जैसे जरूरी कार्यों की स्वीकृति नहीं मिली है जबकि पखवाड़े भर पहले सरपंचों ने जिला प्रशासन के खिलाफमोर्चा खोल धरना देते सुशासन तिहार से अलग कर लिया था जिस पर जिला सीईओ के आश्वासन के बाद धरना खत्म कर दिया लेकिन जिला सीईओ की आश्वासन पूरा होते आज तक जमीन पर नहीं दिखी।

पीएम स्वनिधि योजनांतर्गत स्वनिधि महोत्सव का भव्य आयोजन पथ विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाने पर दिया गया जोर

धमतरी। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत नगर पालिक निगम धमतरी के सभाकक्ष में स्वनिधि महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महापौर जगदीश रामू रोहरा, निगम सभापति कौशिल्या देवांगन, एमआईसी सदस्यों एवं पार्षदगण द्वारा भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी पथ विक्रेताओं एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वित्तीय समावेशन, डिजिटल सशक्तिकरण तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ते हुए उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना था।

इस अवसर पर हितग्राहियों को पीएम स्वनिधि योजना के लाभ, ऋण सुविधा, डिजिटल भुगतान के उपयोग एवं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। महापौर रामू रोहरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा संचालित पीएम स्वनिधि योजना ने लाखों रेहड़ी, पटरी व्यवसायियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। इस योजना के माध्यम से छोटे व्यापारियों को बिना किसी परेशानी के ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है,

जिससे वे अपने व्यवसाय का विस्तार कर आर्थिक रूप से मजबूत बन रहे हैं। उन्होंने हितग्राहियों से योजना का अधिकाधिक लाभ लेने तथा डिजिटल लेन.देन को अपनाने का आह्वान किया।

सभापति कौशिल्या देवांगन ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना केवल ऋण प्रदान करने की योजना नहीं है, बल्कि यह छोटे व्यवसायियों को सम्मानजनक जीवन और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। इस प्रकार के आयोजनों से हितग्राहियों को योजनाओं की विस्तृत जानकारी मिलती है और वे अपने अधिकारों एवं सुविधाओं के प्रति जागरूक होते हैं। कार्यक्रम में एमआईसी सदस्य नरेंद्र रोहरा, विजय मोटवानी, उपायुक्त पी सी सार्वा, पार्षद मेघराज ठाकुर, राकेश चंदवानी, गजेंद्र कंवर, छोटू वर्मा सहित नगर निगम के अधिकारी-कर्मचारी, विभिन्न बैंकों के अधिकारी-कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में योजना के हितग्राही उपस्थित रहे। स्वनिधि महोत्सव के दौरान हितग्राहियों को योजना की विभिन्न सुविधाओं, ऋण वितरण प्रक्रिया, डिजिटल भुगतान प्रणाली एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम का समापन हितग्राहियों के उज्ज्वल भविष्य एवं आर्थिक सशक्तिकरण की शुभकामनाओं के साथ हुआ।

संस्कारों का पतन ही राष्ट्र की मृत्यु है: अंकिता मिश्रा

योगेश फाउंडेशन के तत्वाधान में गौ सम्मान आव्हान अभियान संकल्प कार्यक्रम सम्पन्न

धमतरी। जिस दिन संस्कारों की जड़े सूख जाएंगी, उस दिन समाज तो बचेगा, पर धर्म नही बचेगा। संस्कार ही भारत की आत्मा है और आत्मा की पतन ही राष्ट्र की मृत्यु है। उक्त बातें योगेश फाउंडेशन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों की मातृ शक्तियों की आहुत बैठक में अंकिता रत्नेश मिश्रा ने कही। उक्त बैठक में संस्कारों का पतन और नारी उत्थान के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि कभी यह वही भारत था जहां द्रोपती के वस्त्र हरण पर सभ्यता का शीश झुक गया था और एक स्त्री की लज्जा भंग करने की कोशिश ने महाभारत जैसी भीषण महायुद्ध गाथा को जन्म दिया था। इसी कड़ी में समाज सेविका बासन यादव ने कहा कि आज यह वही भारत है जहां स्त्रियाँ स्वयं अपनी लज्जा का वस्त्र फैशन और आधुनिकता के नाम पर उतार रही है और समाज उसे ग्लैमर कह कर ताली बजा रहा है। प्रसिद्ध रामायणी रमा दीवान ने कहा कि यह भी देश है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने स्त्री

के सम्मान के लिये राज सिंहासन का त्याग किया था, पर आज उसी राम के देश में मर्यादा एक मीम बनकर रह गई है। टीकाकार लक्ष्मी सोनी ने कहा कि जहां पण्डित किसी स्त्री को तिलक लगाने से भी हिचकते थे, वहां अब विवाह जैसे पवित्र अवसरों पर साड़ी पहनाने, ब्लाउज़ फिट करने, मेकप करने और टैटू बनाने तक के कार्य पुरुष कर रहे हैं। कुशल गृहिणी रत्नावली मिश्रा ने इस अवसर पर कहा कि दुख इस बात का नहीं की यह सब हो रहा है, बल्कि इस बात का है कि समाज इसे प्रगति समझ कर गर्व महसूस कर रहा है। कभी मां बहनों के चरण धोकर पुत्र देवता बनते थे, अब वहीं पुत्र जिम और सैलून में खड़े होकर अर्धनग्न महिलाओं की देह छूने को प्रोफेशन मानते हैं। वह भी उन्हीं परिवारों से निकलते हैं जहां संस्कारों की बात करने पर कहा जाता है कि अरे, अब जमाना बदल गया है पर सच यह है कि जमाना नहीं बदला, जमीर मर गया है। धर्म के क्षेत्र में कार्य करने वाली बहन बबली सोनी ने आगे कहा कि जिस समाज में लज्जा मनोरंजन बन जाए, वहां देह संस्कृति से ऊपर चली जाए, जहां स्त्रीत्व का गौरव बाजार में बिके, वहां सभ्यता का सूर्य अस्त हो जाता है। यहां पूजन अब देह का हो रहा है, देवीत्व का नहीं। बैठक में उपस्थित मातृशक्तियों को सम्बोधित करते हुए हेमलता शर्मा ने कहा कि मनुष्य तब नहीं मरता जब उसकी सांस रुकती है, वह तब मरता है जब उसकी शर्म, संकोच और संस्कार मर जाते है। इसी कड़ी में हीरा राजपूत ने आगे कहा कि आज हमारे घरों में माता-पिता धर्म ग्रन्थ नहीं रील्स और रैम्प वॉक देखकर अपने बच्चों को आधुनिकता सिखा रहे हैं। इसी कड़ी में भारती पाण्डे, रेणुका मिश्रा, कोशल मिश्रा, कविता पांडे एवं सीता निषाद ने संयुक्त रूप से कहा कि संस्कारों के पतन का कारण और उसके उपचार के लिए सकारात्मक चिन्तन के साथ मातृशक्तियों को आगे रखकर सब मिलकर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ समाधान और उपचार करेंगे तभी परिवर्तन और परिणाम अवश्य मिलने लगेंगे। योगेश फाउंडेशन के तत्वाधान में पुरुषोत्तम मास की अन्तिम दिवस की समाप्ति और सोमवती अमावस को ध्यान में रखते हुए रिसाई पारा पूर्व, रामसागर पारा, बनिया पारा, पोस्ट ऑफिस वार्ड एवं मराठा पारा के महिला रामायणी प्रमुखों द्वारा भगवान राम के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर विधि-विधान से मंत्रोच्चार द्वारा पूजा, अर्चना कर रामायण की चौपाई का अर्थ बताते हुए सुंदर कांड का पाठ किया गया। कार्यक्रम के अंत में नगर एवं पूरे देश में एक साथ सामूहिक रूप से चलाए जा रहे गो सम्मान आव्हान, अभियान के तहत् भारत में गो हत्या पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगे, गौ हत्या पूर्णतः समाप्त हो, गो माता को राष्ट्र माता, राष्ट्र देव, राष्ट्र आराध्य, राष्ट्र धरोहर के संरक्षण में सामूहिक संकल्प लिया गया। उक्त अवसर पर मुख्य रूप से रत्नावली मिश्रा, हेमलता शर्मा, हीरा राजपूत, रमा दीवान, बासन यादव, भारती पाण्डे, लक्ष्मी सोनी, रेणु मिश्रा, मीरा रजक, कविता पांडे, बबली सोनी, कोशल मिश्रा, अंकिता रत्नेश मिश्रा, सीता निषाद, ऊषा थवाईत, कुमारी सुरेखा राजपूत एवं कुमारी नेहा रजक उपस्थित रहे।

शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के साथ नए शिक्षा सत्र का आगाज

सरायपाली। स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ठ विद्यालय एवं शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में सामुहिक रुप से 16 जून 2026 को शासन के आदेशानुसार शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम आयोजित कर नवप्रवेशी विद्यार्थियों का स्वागत विद्यालय में किया गया। शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के साथ नए शिक्षा सत्र का सुंदर आगाज़ हुआ व्याख्याता द्वय हरिशंकर त्रिपाठी एवं जलंधर वर्गे की अगुवाई में गीत संगीत सहित अतिथियों ने मिलकर पूजन अर्चन,प्रार्थना कार्यक्रम में भाग लिया। तत्पश्चात् सभी अतिथियों का क्रमशः विद्यालय परिवार द्वारा स्वागत- सत्कार,अभिनंदन किया गया। अतिथियों के समक्ष सारगर्भित ढंग से स्वागत भाषण संस्था प्रमुख / प्राचार्य जी.के.अग्रिहे द्वारा दिया गया। कार्यक्रम में टीनू श्रीवास्तव ने विद्यार्थियों को शिक्षण अभिरुचि बढ़ाने प्रोत्साहन स्वरूप कक्षा पहिली से बारहवीं तक कक्षा में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्तकर्ता प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मोमेंटो प्रदान करने की घोषणा की एवं जीवन में मूलभूत कौशल/ दक्षताओं के प्राप्ति के संबंध में प्रकाश डाला। अजय कुमार अग्रवाल ने मितव्ययता हेतू जोर देते हुए मूलभूत संसाधनों की जरूरतों पर बल दिया साथ ही नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों के हित में रुचि लेते हुए स्कूल में पेयजल की समस्या को दूर करने सार्थक पहल करने आश्वस्त किया उन्होंने तात्कालिक रूप से सभी विद्यार्थियों के लिए बिस्किट की व्यवस्था कराया। सांसद प्रतिनिधि एसएमडीसी तारेश्वरी नायक ने कहा कि हमें खुशी है कि हम बच्चों के प्रवेशोत्सव जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होकर अपने स्कूली जीवन को याद कर पा रहे हैं। आप सभी स्कूल में जीवन गढ़ने आए हैं, प्रगति -उन्नति की ओर कदम बढ़ाने,नित्य नवीन सीख हासिल करने आए हैं इसलिए अपने लक्ष्य पर पूरे मनोयोग से फोकस करें,अपने लक्ष्य से आपको भटकना नहीं है,अनावश्यक मोबाईल आदि की लत में पड़ना नहीं है। शिक्षकों के मार्गदर्शन में अपने ज्ञान- कौशल विकास पर ही पूरा ध्यान केन्द्रित करना है। सेजेस एसएमडीसी अध्यक्ष डॉ आशीष दास ने विद्यार्थियों को मेरिट सूची में आने के लिए स्कूल के पहले दिन से ही कमर कसते हुए खूब मेहनत करने और सफ़लता अर्जित करने प्रोत्साहित किया साथ ही विद्यार्थियों के उज्वल भविष्य की सुखद कामना की।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ महतारी एवं शहीद कृष्ण गजानन खोण्डे की प्रतिमा का किया

बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ रमन सिंह आज एक दिवसीय प्रवास पर भाटापारा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाटापारा शहर में छत्तीसगढ़ महतारी एवं शहीद कृष्ण गजानन खोण्डे की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल एवं अधोसंरचना विकास मण्डल के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव,छत्तीसगढ़ राज्य साहकरी बैंक के अध्यक्ष केदारनाथ गुप्ता,पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा उपस्थित थे। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सिंह ने छत्तीसगढ़ महतारी चौक में नवनिर्मित छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पूजा -अर्चना कर नमन किया। इसके पश्चात भाटापारा स्थित शहीद कृष्ण गजानन खोण्डे परिसर में शहीद कृष्ण गजानन खोण्डे की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने देश के लिये सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूत फ्लाइट लेफ्टिनेंट शहीद कृष्ण गजानन खोन्डे जिन्होंने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे,उन्हें पुण्य स्मरण किया।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस परिसर पर स्थापित शहीद कृष्ण गजानन खोण्डे की प्रतिमा आने वाले पीढी के युवाओं के लिये प्रेरणा बनेगी।उन्होंने इस अवसर पर शहीद के परिजनों से आत्मीय भेंट किया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष आकांक्षा जायसवाल, नगर पालिका अध्यक्ष अश्वनी शर्मा, कलेक्टर कुलदीप शर्मा,पुलिस अधीक्षक ओपी शर्मा, जिला अध्यक्ष आनंद यादव,जनपद अध्यक्ष सविता अनंत पूर्व विधायक डॉ.सनम जांगड़े, शहीद कृष्ण गजानन खोण्डे के परिजनों में सुपुत्री प्रिया खोण्डे,भाई प्रभाकर खोण्डे सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में नगरवासी उपस्थित रहे।

छात्र छात्राओं का तिलक लगाकर,मुह मीठा कर दुलारपाली स्कूल में मना प्रवेशोत्सव

सरायपाली। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दुलारपाली में नए शिक्षा सत्र के प्रथम दिवस पर 'शाला प्रवेशोत्सव' का भव्य आयोजन किया गया।कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पारसमणी पटेल द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। विद्यार्थियों ने समूह स्वर में सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। इसके पश्चात, मुख्य अतिथि पारसमणी पटेल विद्यालय के प्राचार्य एवं समस्त शिक्षकों के साथ मिलकर स्कूल पहुंचे नए पुराने सभी छात्र-छात्राओं का तिलक लगाकर, माला पहनाकर व मुंह मीठा कराकर आत्मीय स्वागत किया। शासन की मंशानुरूप, सत्र के पहले ही दिन नव-प्रवेशी छात्रों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक और शिक्षण सामग्री वितरित की गई। इस अवसर पर प्राचार्य प्रेमानन्द भोई ने अपने उद्बोधन में छात्रों को नियमित शाला आने और कड़ी मेहनत कर उज्ज्वल भविष्य बनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में मिष्ठान्न के साथ बिस्किट नेवता भोज के रूप में दिया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं एवं शिक्षक गण उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन टेकलाल पटेल ने किया।

निगम आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी

धमतरी। जनसुविधा के कार्यों, शासन के महती योजनाओं के क्रियान्वयन में उदासीनता, शिथिलता सहित अनेक मुद्दों को लेकर कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने नगर निगम आयुक्त को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है जिसमें लिखा है कि 1 जून 2026 से 12 जून 2026 तक स्वीकृत अवकाश के पूर्व दिनांक 29 मई 2026 से 31 मई 2026 तक आकस्मिक अवकाश के लिये आवेदन प्रस्तुत कर अवकाश पर प्रस्थान करते समय यह निर्देशित किया गया था कि महती आवश्यकता के कार्यों के लिये सतत टेलिफोनिक संपर्क में रहेंगे और नगर निगम क्षेत्रांतर्गत नाले नालियों की वर्षा पूर्व सफाई कराने, मलबों को हटाकर जल निकासी की समुचित व्यवस्था तथा वर्षा काल में सड़े गले फलों के बिक्री के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही, आवारा पशुओं के प्रबंधन, वर्षा ऋतु के पूर्व निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने के संबंध में समय समय पर दिये गये निर्देशानुसार आवश्यक व्यवस्था एवं दायित्व सुनिश्चित कर अवकाश पर प्रस्थान करेंगे। लेकिन आपके द्वारा उपरोक्त दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया। नगर निगम आयुक्त मति प्रिया गोयल को 12 जून 2026 को कलेक्टर कार्यालय के पत्र क्रमांक 6043/वलि-1/2026 प्रेषित करते हुए यह भी कहा गया है कि मानसून 2026 बाढ़ राहत आपदा की व्यवस्था के संबंध में संपन्न बैठक दिनांक 11 मई 2026 में दिये गये निर्देशों का पालन भी नहीं किया गया, जिले में मानूसन पूर्व वर्षा आरंभ हो गया है किंतु अभी भी निगम क्षेत्र के नाले नालियों की सफाई कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, जल निकासी व्यवस्था व्यवस्थित नहीं की गई है, राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि अंतर्गत वर्ष 2025-26 में स्वीकृत पुलिया, नाली, रैन वॉटर हार्वेस्टिंग जैसे महत्वपूर्ण एवं जनसुविधा के कार्य भी आज की स्थिति में अपूर्ण है। उपयुक्त स्थिति पर आपके विरूद्ध जनसामान्य तथा नगरीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा भेंट में

इस मामले को लेकर निगम आयुक्त प्रिया गोयल के मोबाईल नंबर 7000827132 में दोपहर 2.29 बजे संपर्क कर उनका पक्ष लिये जाने का प्रयास किया गया परंतु उन्होंने मोबाईल रिसीव नहीं किया जिस कारण उनका पक्ष नहीं लिया जा सका। इस संबंध में महापौर रामू रोहरा से दूरभाष पर चर्चा किये जाने पर उनका कहना था कि निश्चित रूप से जिले के संवेदनशील कलेक्टर अबिनाश मिश्रा द्वारा आयुक्त को जारी कारण बताओ सूचना पत्र शहर विकास के लिये आवश्यक हो गया था क्योंकि लगातार आयुक्त के अनुपस्थिति और उनके अड़ियल रवैये से निगम का कार्य बाधित हो रहा है जिससे शहर के नागरिकों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। रोहरा ने उम्मीद की है कि कलेक्टर के सहयोग से धमतरी के विकास को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जायेगा और निगम में व्याप्त समस्याओं को दूर करते हुए स्वच्छता के मामले में व्यापक कार्य किये जायेंगे।

शिकायत तथा आपके कार्य के प्रति असंतोष व्यक्त किया जाता है। कारण बताओ सूचना पत्र में यह भी दर्शित है कि शासन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिये त्वरित कार्यवाही के निर्देश समय समय पर दिये गये हैं तथापि वर्तमान स्थिति में वर्ष 2020 से 2025 तक के 14 प्रकरणों में आपके द्वारा जवाब, दावा ही प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण प्रकरण लंबित है। इससे प्रतीत होता है कि आप अपने पदीय दायित्वों को पूर्ण क्षमता, सन्निष्ठा एवं तत्परता से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। कारण बताओ सूचना पत्र में यह भी उल्लेखित है कि जनसुविधा के कार्यों, शासन की महती योजनाओं के क्रियान्वयन में उदासीनता एवं शिथिलता बरत रहे हैं।

यह स्थिति अत्यंत खेदजनक है तथा छग सिविल सेवा आचरण नियम 1965, छग सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 1,2 एवं 3 के विपरीत है। अतएव आप कारण स्पष्ट करें कि उपरोक्त कृत्य के लिये क्यों न आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाये। आप अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के दो दिवस के भीतर समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। नियत समयावधि में एवं संतोषजनक जवाब प्राप्त न होने की दशा में आपके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। धमतरी जिले के विकास को लेकर दृढ़ संकल्पित, संवेदनशील कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के कारण बताओ सूचना पत्र की जानकारी शहर के नागरिकों को लगी तो उनमें खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कलेक्टर के पत्र में धमतरी शहर की अनेक समस्याएं जो नागरिकों द्वारा लगातार उठाई जा रही थी, कार्यवाही नहीं होने के कारण नागरिक ऐसी समस्याओं से लगातार जूझ रहे थे। अब जब आयुक्त की हठधर्मिता से संबंधित वार्डों में नाली, नाले, गंदगी, इत्यादि समस्याएं विद्यमान हैं, कलेक्टर के द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र से अब शहरवासियों को यह उम्मीद जगी है कि उनकी उपरोक्त समस्याओं के निराकरण का रास्ता खुल जायेगा और शहर स्वच्छता की ओर बढ़ेगा।

मुजगहन विद्यालय में शाला प्रवेश उत्सव संपन्न, नवप्रवेशी विद्यार्थियों का स्वागत

धमतरी। शासकीय विद्यालय मुजगहन में शाला प्रवेश उत्सव हर्षोल्लास एवं उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजयुमो जिला महामंत्री एवं शाला विकास समिति के अध्यक्ष ओमेश यादव रहे। कार्यक्रम में वरिष्ठ शिक्षक नाग सर, प्राचार्य मोनिका गोस्वामी, समस्त शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में पालकों की उपस्थिति रही। इस अवसर पर नवप्रवेशी विद्यार्थियों का तिलक लगाकर एवं पुष्प भेंट कर आत्मीय स्वागत किया गया। साथ ही विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य.पुस्तकों का वितरण भी किया गया, जिससे वे सत्र के प्रारंभ से ही अपनी पढ़ाई सुचारु रूप से प्रारंभ कर सकें। विद्यार्थियों को शिक्षा के महत्व से अवगत कराया गया तथा नियमित रूप से विद्यालय आने के लिए प्रेरित किया गया। अपने संक्षिप्त उद्बोधन में ओमेश यादव ने कहा कि शिक्षा बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला है। उन्होंने पालकों से अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने का आग्रह किया तथा विद्यार्थियों को मन लगाकर अध्ययन करने और जीवन में उच्च लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने, अधिक से अधिक बच्चों को विद्यालय से जोड़ने तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संकल्प को दोहराया गया। सभी अतिथियों, शिक्षकों एवं पालकों के सहयोग से शाला प्रवेश उत्सव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

संक्षिप्त समाचार

जिला अस्पताल में प्रसव के दौरान महिला और नवजात की मौत

रायपुर। सूरजपुर जिला चिकित्सालय परिसर स्थित मातृत्व एवं शिशु अस्पताल में प्रसव के दौरान एक गर्भवती महिला और उसके गर्भ में पल रहे नवजात की मौत हो जाने से हड़कंप मच गया। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। जानकारी के अनुसार, महिला को प्रसव के लिए जिला अस्पताल के मातृत्व-शिशु अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि यह उसका पहला प्रसव था। प्रसव प्रक्रिया के दौरान महिला को एक इंजेक्शन लगाया गया, जिसके बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। कुछ ही देर में महिला की मौत हो गई। गर्भ में पल रहे शिशु को भी चिकित्सक नहीं बचा सके। घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। परिजनों ने उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सकों का कहना है कि प्रसव से पूर्व इंजेक्शन लगाए जाने के दौरान महिला को उल्टी हुई थी। चिकित्सकों के अनुसार उल्टी श्वास नली में फंस जाने से उसे सांस लेने में गंभीर समस्या हुई, जिसके चलते उसकी हालत तेजी से बिगड़ गई और उपचार के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी।

युवक की निर्मम हत्या, गली में मिला खून से लथपथ शव

रायपुर। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के नयापारा स्थित गणेश नगर में मंगलवार सुबह एक युवक का खून से लथपथ शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। गली के बीचों-बीच शव पड़े होने की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान गणेश नगर निवासी इरफान बघीरा के रूप में हुई है। सुबह जब मोहल्ले के लोग घरों से बाहर निकले तो उन्होंने गली में युवक का शव पड़ा देखा। शव के आसपास बड़ी मात्रा में खून फैला हुआ था, जिसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही सिरगिट्टी पुलिस, डॉग स्क्वायड और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान पुलिस ने शव के पास से खून से सने सीमेंट के दो बड़े पोलनुमा पत्थर बरामद किए हैं। आशंका जताई जा रही है कि आरोपियों ने इन्हीं भारी पत्थरों से हमला कर युवक की हत्या की है।

मोदी सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए:अमित

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री अमित साहू ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों को देश के इतिहास का सबसे कल्याणकारी दौर बताया है। साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का हर एक दिन 'राष्ट्र प्रथम' और 'गरीब कल्याण' को समर्पित रहा है। बिना किसी राजनीतिक वंशवाद के, एक सामान्य पृष्ठभूमि से आकर देश के सर्वोच्च पद पर लगातार तीन बार जनविश्वास हासिल करना मोदी की नीति और नीयत की जीत है। भाजपा प्रदेश मंत्री साहू ने कहा कि पिछले 12 सालों में सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं ने देश के अन्तिम व्यक्ति तक गरिमापूर्ण जीवन पहुँचाया है। नीति आयोग के आँकड़ों के मुताबिक मोदी के कार्यकाल में लगभग 25 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं। साहू ने छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात रखते हुए कहा कि देश में बने 58 करोड़ से अधिक जनधन खाते, 12 करोड़ से अधिक शौचालय, 10 करोड़ से अधिक उज्ज्वला गैस कनेक्शन और आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपये का मुफ्त इलाज, देश के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के लाखों गरीब परिवारों के लिए सुरक्षा कवच बना है। मोदी के ये 12 वर्ष 'विश्वास, विकास और जनकल्याण' की अविरल यात्रा हैं।

कर्ज चुकाने के लिए बने लुटेरे, बैंक मित्र और वाइस सेंटर संचालकों को निशाना बनाने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार

रायपुर। अभनपुर थाना क्षेत्र में बैंक मित्रों और च्वाइस सेंटर संचालकों से लाखों रुपये की लूट करने वाले चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से लूटी गई नकदी, दो बाइक, चार मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल किए गए दो चाकू बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने ग्राम सारखी और हसदा क्षेत्र में दो अलग-अलग लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था। पहली घटना में बैंक ऑफ बड़ौदा के बैंक मित्र पोषण लाल साहू से करीब 2 लाख रुपये लूट लिए गए थे। पीड़ित बैंक से राशि लेकर घर लौट रहा था, तभी पुलिया के पास आरोपियों ने उसका रास्ता रोक लिया। बदमाशों ने चेहरे पर मिर्ची पाउडर फेंककर चाकू की नोक पर नकदी से भरा बैग और मोबाइल फोन लूट लिया। इसके बाद आरोपियों ने हसदा क्षेत्र में च्वाइस सेंटर संचालक उमेन्द्र कुमार देवांगन को निशाना बनाया। बाइक सवार बदमाशों ने चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और करीब 1.50 लाख रुपये से भरा बैग लेकर फरार हो गए।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किया कचना धुरवा गोंडवाना भवन का लोकार्पण

जनजातीय गौरव को सहेजते हुए विकास के नए आयाम गढ़ रही सरकार

■ अपनी जड़ों से जुड़कर आगे बढ़ेगा समाज , विकास में सरकार हर कदम पर साथ - मुख्यमंत्री श्री साय

रायपुर/ संवाददाता

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज गरियाबंद जिले के ग्राम दर्रापारा में अखिल भारतीय गोंडवाना गोंड महासभा केंद्रीय समिति बिन्द्रानवागढ़ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 1 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से निर्मित कचना धुरवा गोंडवाना भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर आदिवासी परंपरा के अनुरूप मुख्यमंत्री का पगड़ी पहनाकर एवं पीला चावल से तिलक लगाकर आत्मीय स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम स्थल स्थित आदिवासी देवस्थल देवठाना में पारंपरिक विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के अंतर्गत पीपल का पौधा रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। इस अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं समाज के प्रतिनिधियों ने भी वृक्षारोपण किया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि कचना धुरवा की यह पवित्र भूमि आदिवासी समाज की आस्था, संस्कृति और गौरवशाली विरासत का प्रतीक है। उन्होंने गोंडवाना भवन के निर्माण के लिए समाज को बधाई देते हुए कहा कि यह भवन सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सामुदायिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा तथा नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और परंपराओं से

जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से बनी सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के अनुरूप निरंतर कार्य कर रही है। बीते ढाई वर्षों में गरीब, किसान, महिला, युवा और जनजातीय समाज के उत्थान के लिए अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रदेश में 18 लाख गरीब परिवारों को आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 10 लाख 60 हजार से अधिक आवास पूर्ण हो चुके हैं। प्रतिदिन लगभग 1600 आवासों का निर्माण किया जा रहा है। किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान का मूल्य मिल रहा है, तेंदूपत्ता संग्राहकों को 5500 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से भुगतान किया जा रहा है तथा महतारी वंदन योजना के तहत लगभग 70 लाख महिलाओं के खातों में प्रतिमाह एक हजार रुपए की राशि अंतरित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय गरियाबंद और बस्तर क्षेत्र नक्सलवाद की चुनौती से प्रभावित थे, लेकिन आज यहां शांति, सुरक्षा और विकास का वातावरण निर्मित हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों और सुरक्षा बलों के प्रयासों से विकास की नई तस्वीर उभर रही है। नियद नेल्लानार योजना के माध्यम से दूरस्थ गांवों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि श्रीरामलला दर्शन योजना के माध्यम से अब तक 42 हजार से अधिक श्रद्धालु अयोध्या धाम के दर्शन कर चुके हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के जरिए भी प्रदेशवासियों को विभिन्न धार्मिक स्थलों के दर्शन का अवसर मिल रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि सरचार्ज माफी का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता नजदीकी बिजली कार्यालय में पंजीयन कराएं। प्रदेश में अब तक 757 करोड़ रुपए से अधिक की राशि माफ की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि अटल डिजिटल सेवा केंद्रों के माध्यम से आम नागरिकों को आय, जाति, निवास सहित विभिन्न प्रमाण पत्र आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 का उल्लेख करते हुए कहा कि शासन की मंशा आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है।

प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में 24 को होगी ग्राम सभा

■ आवास प्लस 2.0 की स्थायी प्रतीक्षा सूची सहित विभिन्न विषयों पर होगी चर्चा

रायपुर। संवाददाता

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों को ग्राम सभाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास, पंचायतों की वित्तीय स्थिति, आवास योजनाओं, रोजगार, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय विकास कार्यों जैसे जनहित से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा एवं निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। छत्तीसगढ़ के सभी ग्राम पंचायतों में 24 जून 2026 को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा।ग्राम सभाओं में आवास प्लस 2.0 की स्थायी प्रतीक्षा सूची सहित विभिन्न विषयों पर होगी चर्चा की जाएगी। ग्राम सभा में विशेष रूप से आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण से प्राप्त सिस्टम जनरेटेड स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) का अवलोकन एवं वाचन किया जाएगा। ग्राम सभा द्वारा शासन की मार्गदर्शिका एवं एसओपी के अनुसार पात्र हितग्राहियों की प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी तथा ग्रामीणों से प्राप्त दावे-आपत्तियों को नियमानुसार प्राप्त कर निराकरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ग्राम सभा से अनुमोदन के बाद स्थायी प्रतीक्षा सूची को आवास सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा। ग्राम सभा में पूर्व बैठक के निर्णयों के पालन प्रतिवेदन, पंचायतों के आय-व्यय की समीक्षा एवं अनुमोदन, विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्यों की प्रगति, तथा अन्य विकासात्मक विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। ग्राम सभाओं में विकसित भारत, रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी जी राम जी) के संबंध में भी ग्रामीणों को जानकारी दी जाएगी तथा इसके क्रियान्वयन पर चर्चा होगी। योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन किए जाने, बेरोजगारी भत्ते के बेहतर प्रावधान, समय पर मजदूरी भुगतान और ग्राम सभा आधारित विकास योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।

छोटे नेताओं की बलि देकर बड़े चेहरों के अपराधों पर पर्दा डाल रही कांग्रेस : भाजपा

रायपुर। भाजपा सोशल मीडिया प्रदेश संयोजक मितुल कोठारी ने कोण्डागाँव मामले में कांग्रेस द्वारा की गई कार्रवाई को महज एक राजनीतिक ढोंग और जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास बताया है। कोठारी ने कहा कि कोण्डागाँव में आपराधिक मामला दर्ज होते ही कांग्रेस ने अपने छोटे नेता को बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन पार्टी के बड़े नेताओं पर लगे गंभीर आरोपों पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने रहस्यमयी चुप्पी साध रखी है! कोठारी ने पार्टी के सोशल मीडिया पर जारी पोस्टर के जरिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज से सीधे सवाल दागते हुए पूछा कि आखिर भूपेश बघेल, देवेंद्र यादव और कवासी लखमा जैसे नेताओं पर फैसला कब होगा?

खुशहाली की नई पौध-समय पर खाद-बीज

दंडवन के किसान रुद्रेश्वर के हौसलों को लगी नई उड़ान

रायपुर/ संवाददाता

कृषि आदानों (खाद और बीज) की समय पर उपलब्धता किसानों की राह बेहद आसान बनाती है। इससे न केवल उत्पादकता में वृद्धि होती है, बल्कि कृषि लागत और मेहनत भी कम होती है। छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी नीतियों और जिला प्रशासन की मुस्तैदी का सीधा असर अब प्रदेश के खेतों में दिखने लगा है। खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ ही धान के कटोरे में अन्नदाताओं के चेहरों पर मुस्कान तैरने लगी है। इसकी एक बानगी नारायणपुर जिले के ग्राम दंडवन में देखने को मिली है, जहाँ समय पर कृषि आदानों (खाद-बीज) की उपलब्धता ने किसानों की राह बेहद आसान कर दी है। ग्राम दंडवन के प्रगतिशील किसान रुद्रेश्वर चौहान के पास लगभग 5 एकड़ कृषि भूमि है, जहाँ वे हर साल पारंपरिक और वैज्ञानिक पद्धतियों के समन्वय से धान और अन्य खरीफ फसलों की खेती करते हैं। इस साल मानसून की दस्तक के साथ ही रुद्रेश्वर को उनकी जरूरत के मुताबिक उन्नत बीज और पर्याप्त मात्रा में खाद समय पर उपलब्ध करा दी गई है। समय पर मिले इस सहयोग से उत्साहित रुद्रेश्वर अब पूरी ऊर्जा के साथ अपने खेतों को संवारने और बुवाई की तैयारियों में जुट गए हैं। रुद्रेश्वर चौहान केवल एक सामान्य किसान नहीं, बल्कि क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए प्रेरणास्रोत भी हैं। उन्होंने कहा कि पिछले सीजन में मैंने सही कृषि प्रबंधन और कड़ी मेहनत के दम पर 85 क्विंटल धान का रिकॉर्ड उत्पादन किया था। जब इस उपज को बेहतर व्यवस्था के बीच विक्रय किया, तो उससे मिली अच्छी आय ने मेरे पूरे परिवार की तकदीर बदल दी।

बिजली दरों में संशोधन से आम उपभोक्ताओं पर न्यूनतम असर

रायपुर। संवाददाता

छत्तीसगढ़ में विद्युत टैरिफ के वार्षिक संशोधन के बावजूद छत्तीसगढ़ सरकार ने आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार को न्यूनतम रखने के लिए कई स्तरों पर राहत और संरक्षण की व्यवस्था की है। विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए औसतन 6.23 प्रतिशत अर्थात लगभग 42 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि स्वीकृत की गई है, लेकिन राज्य में मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत योजना, बिजली बिल समाधान योजना और पीएम सूर्यघर योजना जैसी पहलों के कारण अधिकांश उपभोक्ताओं पर इसका प्रभाव काफी सीमित रहेगा। गौरतलब है कि विद्युत दरों का निर्धारण छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा किया जाता है, जो एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। आयोग विद्युत कंपनियों की वार्षिक राजस्व आवश्यकता, उत्पादन लागत, कोयला, ट्रांसमिशन तथा वितरण व्यय सहित विभिन्न आर्थिक पहलुओं का अध्ययन कर दरों का निर्धारण करता है। नए टैरिफ में घरेलू उपभोक्ताओं की दरों में 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट तक की वृद्धि की गई है। हालांकि मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत योजना के कारण प्रदेश के अधिकांश परिवारों पर इसका अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। प्रदेश में लगभग 51 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं। इनमें से 14.5 लाख बीपीएल परिवारों को 30 यूनिट तक बिजली निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है, जिसका पूरा खर्च राज्य सरकार वहन कर रही है। इसके अलावा 26.5 लाख ऐसे उपभोक्ता, जिनकी मासिक खपत 400 यूनिट तक है, उन्हें 200 यूनिट तक की खपत पर 50 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। इन राहतों के कारण लगभग 41 लाख घरेलू उपभोक्ताओं पर बिजली दर वृद्धि का प्रभाव शून्य से लेकर मात्र 3.65 प्रतिशत तक ही होगा। राज्य के 8.65 लाख कृषि उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा प्रभार में 40 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है, लेकिन इसकी प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा सब्सिडी के रूप में किए जाने के कारण किसानों पर इसका अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। कृषि पंपों के स्थायी प्रभार को भी यथावत रखा गया है। ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित पीएम सूर्यघर योजना का छत्तीसगढ़ राज्य में तेजी से क्रियान्वयन किया जा रहा है।

नैनो यूरिया और नैनो डीएपी से किसान मनोहर यादव की खेती बनी अधिक लाभकारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कृषि क्षेत्र में नवाचार और वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयास किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम कचंदा निवासी किसान मनोहर यादव इसकी एक प्रेरणादायक मिसाल हैं। नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के उपयोग से उन्होंने अपनी खेती की लागत कम करने के साथ-साथ उत्पादन और आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है। लगभग दो एकड़ भूमि पर खेती करने वाले यादव पहले बढ़ती कृषि लागत और उत्पादन की अनिश्चितता से चिंतित रहते थे। कृषि विभाग के तकनीकी मार्गदर्शन तथा राज्य शासन की किसान हितैषी पहलों से प्रेरित होकर उन्होंने पारंपरिक खेती के साथ आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने का निर्णय लिया और अपनी फसलों में नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी का प्रयोग शुरू किया। नई तकनीक के परिणाम शीघ्र ही सामने आने लगे। नैनो उर्वरकों के उपयोग से फसलों को संतुलित पोषण मिला, जिससे पौधों की वृद्धि बेहतर हुई और उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई। साथ ही उर्वरकों पर होने वाला खर्च भी कम हुआ, जिससे खेती की लागत नियंत्रित करने में मदद मिली।

पीएम स्वनिधि योजना से लघु व्यवसायियों का बढ़ रहा आत्मविश्वास

■ ऋण सहायता से स्वरोजगार को मिल रहा विस्तार, आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हितग्राही

रायपुर/ संवाददाता

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में छोटे व्यापारियों एवं पथ विक्रेताओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में प्रभावी कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से रेहड़ी-पटरी एवं फुटकर व्यवसाय से जुड़े लोगों को बिना किसी जटिल प्रक्रिया के ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे वे अपने व्यवसाय का विस्तार कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। प्रदेशभर में संचालित विशेष शिविरों और जनसंपर्क गतिविधियों के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को योजना से जोड़ने का कार्य लगातार किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे छोटे व्यवसायियों को आवश्यक कार्यशील पूंजी प्राप्त हो रही है और उनके कारोबार को नई गति मिल रही है।बलरामपुर जिले के ग्राम जतरो निवासी श्री उमाचंद सिंह इसकी प्रेरणादायक मिसाल हैं। फल विक्रय का कार्य करने वाले श्री उमाचंद सिंह को व्यवसाय विस्तार के लिए पूंजी की आवश्यकता थी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत उन्हें पहले 10 हजार रुपये की ऋण सहायता मिली थी, जिसका समय पर उपयोग और पुनर्भुगतान करने के बाद उन्हें 25 हजार रुपये का ऋण स्वीकृत हुआ। इस राशि से वे अपने व्यवसाय के लिए आवश्यक सामग्री की उपलब्धता बढ़ा रहे हैं तथा ग्राहकों की मांग के अनुरूप बेहतर सेवाएं देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। श्री उमाचंद सिंह का कहना है कि योजना से प्राप्त ऋण ने उनके व्यवसाय को नई मजबूती दी है। पहले सीमित पूंजी के कारण उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब वे अपने कारोबार को अधिक व्यवस्थित ढंग से संचालित कर पा रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि इससे उनकी आय में भी निरंतर वृद्धि होगी। प्रदेश में जिला प्रशासनों द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार विशेष शिविर आयोजित कर पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋण प्रकरणों का पंजीयन, नवीन आवेदन, ऋण स्वीकृति एवं वितरण की प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है। साथ ही हितग्राहियों को डिजिटल भुगतान एवं वित्तीय साक्षरता के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना न केवल छोटे व्यवसायियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहभागी बनने का अवसर भी दे रही है।

राज्य नीति आयोग और यूनिसेफ के बीच उच्चस्तरीय बैठक

विकसित छत्तीसगढ़ एवं बस्तर अंजोर को मिला अंतरराष्ट्रीय समर्थन-उपाध्यक्ष गणेश शंकर मिश्रा

रायपुर/ संवाददाता

राज्य नीति आयोग, छत्तीसगढ़ के उपाध्यक्ष श्री गणेश शंकर मिश्रा से आज यूनिसेफ इंडिया के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने नीति भवन नवा रायपुर में सौजन्य भेंट की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व यूनिसेफ इंडिया की फील्ड सेवा प्रमुख सुश्री सोलेदाद हेरेरो ने किया। इस अवसर पर यूनिसेफ छत्तीसगढ़ फील्ड कार्यालय की प्रमुख श्रीमती सीमा कुमार एवं सामाजिक नीति प्रमुख डॉ. बाल परितोष दाश भी उपस्थित रहे। बैठक में विकसित छत्तीसगढ़ प्रगति फ्रेमवर्क, बाल कल्याण सूचकांक, बच्चों के लिए सार्वजनिक वित्त, सामुदायिक जागरूकता एवं सामाजिक व्यवहार परिवर्तन और बस्तर अंजोर कार्यक्रम पर विस्तृत चर्चा हुई।बैठक में राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री मिश्रा ने स्पष्ट किया कि विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना में बच्चे केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि राज्य के विकास की आधारशिला हैं। उन्होंने कहा कि जब तक राज्य के प्रत्येक बच्चे को स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और संरक्षण सुनिश्चित नहीं होता, तब तक विकसित छत्तीसगढ़ का लक्ष्य अधूरा है। राज्य नीति आयोग ने विकसित छत्तीसगढ़ प्रगति फ्रेमवर्क के अंतर्गत 50 से अधिक विभागों के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतक विकसित किए हैं, जिसमें बाल कल्याण को एक स्वतंत्र एवं समर्पित विषयक्षेत्र के रूप में सम्मिलित किया गया है। राज्य नीति आयोग एवं यूनिसेफ के संयुक्त प्रयास से स्थापित विकसित छत्तीसगढ़ सामाजिक नीति सहयोग इकाई राज्य में साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण संस्थागत पहल है। यह इकाई विकसित छत्तीसगढ़ प्रगति फ्रेमवर्क, बाल कल्याण सूचकांक, बच्चों के लिए बजट विश्लेषण और सामाजिक संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए राज्य के विभागों को निरंतर तकनीकी सहयोग प्रदान करती है। बैठक में इस इकाई के कार्यों की सराहना की गई और इसे और अधिक सशक्त बनाने पर सहमति व्यक्त की गई। राज्य नीति आयोग देश में पहली बार एक राज्य-विशिष्ट बाल कल्याण मापन पद्धति एवं बाल वंचना सूचकांक विकसित करेगा। यह सूचकांक राज्य के विभागों को बच्चों तक सेवा वितरण की कमियों की पहचान करने और बाल-केंद्रित नीतियों को सुदृढ़ करने में सहायक होगा।

संपादकीय

सशक्तिकरण के दावों के बीच महिलाओं के खिलाफ हिंसा की कड़वी हकीकत

शहरों की तुलना में शांतिप्रिय माने जाने वाले गांवों में महिलाओं को घरेलू एवं यौन हिंसा का ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। यह स्थिति तब है, जब ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को सशक्त करने के लिए कागजों में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।देश में महिला सशक्तिकरण को लेकर अक्सर बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं। सरकार की ओर से इस दिशा में कई महत्वपूर्ण योजनाएं और अभियान शुरू किए गए हैं। सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक कार्यों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। महिलाओं को विधायिका में तैंतीस प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही जा रही है।यही नहीं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष कानून भी बनाए गए हैं। मगर, जमीनी हकीकत यह है कि महिलाएं खुद को कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं। घर हो या बाहर, हर जगह उन्हें हिंसा का भय सताता रहता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 की रिपोर्ट के आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं। इसके मुताबिक, ग्रामीण इलाकों में हर चौथी और शहरी क्षेत्र में हर छठी महिला किसी न किसी रूप में हिंसा का शिकार हो रही है।यानी शहरों की तुलना में शांतिप्रिय माने जाने वाले गांवों में महिलाओं को घरेलू एवं यौन हिंसा का ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। यह स्थिति तब है, जब ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को सशक्त करने के लिए कागजों में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।देश में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा कई रूपों में सामने आती है। इनमें घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना और जादू-टोने जैसे अंधविश्वास के कारण मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न प्रमुख हैं। नए सर्वेक्षण में 18 से 49 वर्ष आयु वर्ग की विवाहित महिलाओं में से 22 प्रतिशत से अधिक ने माना कि उन्होंने अपने जीवन में कभी न कभी घरेलू हिंसा का सामना किया है। हालांकि यह आंकड़ा पिछले सर्वेक्षण की तुलना में कुछ कम है, लेकिन यह अब भी एक बड़ी सामाजिक चुनौती की ओर इशारा करता है।सवाल है कि जब महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर अंकुश लगाने के लिए अलग से कानून बनाए गए हैं, तो फिर इस तरह की घटनाओं का सिलसिला थम क्यों नहीं रहा है? जाहिर है कि इन कानूनों का प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों की लापरवाही और ढुलमुल रवैये का ही नतीजा है कि महिलाएं न तो अपने घर पर और न ही बाहर खुद को सुरक्षित महसूस कर पाती हैं।सर्वेक्षण में 18 से 29 वर्ष आयु वर्ग की 0.7 प्रतिशत महिलाओं का कहना है कि 18 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले वे यौन हिंसा का शिकार हुई थीं। शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा 0.4 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 0.8 प्रतिशत दर्ज किया गया है। इससे साफ है कि गांवों में यौन हिंसा की स्थिति शहरों के मुकाबले ज्यादा भयावह है। इसकी एक बड़ी वजह ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता की कमी और कानूनी जानकारी का अभाव है।

विशेष बात यह है कि इस व्यस्तता के बीच भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यप्रदेश को प्राथमिकता की सूची में सदैव रखा। उन्हें जब भी मौका मिला, वे मध्यप्रदेश आए और जनता का भला कर गए। वे जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसान हैं। कृषि प्रधान राज्य मध्यप्रदेश के लाखों किसान अपनी मेहनत से देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। उनकी समृद्धि और कल्याण के बिना देश की प्रगति अधूरी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की राज्य सरकार ने किसानों के उत्थान के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। इन प्रयासों में बीमा, सिंचाई, फसल विविधीकरण, आधुनिक तकनीक, बाजार सुविधाओं और किसानों की आय दुगनी करने पर पर विशेष जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मोहन यादव सरकार के संयुक्त प्रयासों से प्रदेश में किसानों के कल्याण के लिए अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं।

पीएम मोदी के 12 साल और सीएम यादव का विजन, कैसे बदल रही एमपी के 84 लाख किसानों की तकदीर

(आकाश सिकरवार)

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने साल 2026 को 'कृषि कल्याण वर्ष' घोषित कर किसानों के लिए खजाना खोल दिया है। गेहूं खरीदी का लक्ष्य 100 लाख मीट्रिक टन करने से लेकर भूमि अधिग्रहण पर 4 गुना मुआवजे जैसे ऐतिहासिक फैसलों से राज्य की कृषि वृद्धि दर 16 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास-सबका प्रयास, का मंत्र देने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद संभालते ही अन्नदाता के कल्याण का स्वप्न देखा था। इस स्वप्न के साथ विकास के अन्य कार्य करते-करते उन्होंने किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं संचालित कीं। आज उन्होंने अपने कार्यकाल के सफलतम 12 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इसके मद्देनजर यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि उनके कार्यकाल में किसानों का भला हुआ है। इन 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार खुद को ग्लोबल लीडर भी सिद्ध किया है। कई मौकों पर विश्व के बड़े राष्ट्रों के अध्यक्षों को प्रधानमंत्री मोदी से मशवरा करते देखा गया है।

विशेष बात यह है कि इस व्यस्तता के बीच भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यप्रदेश को प्राथमिकता की सूची में सदैव रखा। उन्हें जब भी मौका मिला, वे मध्यप्रदेश आए और जनता का भला कर गए। वे जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसान हैं। कृषि प्रधान राज्य मध्यप्रदेश के लाखों किसान अपनी मेहनत से देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। उनकी समृद्धि और कल्याण के बिना देश की प्रगति अधूरी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की राज्य सरकार ने किसानों के उत्थान के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। इन प्रयासों में बीमा, सिंचाई, फसल विविधीकरण, आधुनिक तकनीक, बाजार सुविधाओं और किसानों की आय दुगनी करने पर पर विशेष जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मोहन यादव सरकार के संयुक्त प्रयासों से प्रदेश में किसानों के कल्याण के लिए अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं।

किसान सम्मान निधि से अन्नदाता हुआ खुशहाल - केन्द्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है। इसके तहत सभी भूमि धारक किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रू की आय सहायता तीन समान किस्तों में सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। मध्यप्रदेश में लाखों किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इसी तरह मध्यप्रदेश सरकार भी किसानों को 6000 रुपये महीने देती है। इससे किसानों को जीवन संचालित करने में आसानी होती है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत भी 84 लाख से अधिक किसानों के खातों में 20,878 करोड़ रु से अधिक की राशि का अंतरण किया जा चुका है।

गेहूं उपार्जन में रिकॉर्ड उपलब्धि - वर्ष 2026-27 में गेहूं उपार्जन के लिए प्रदेश के 19 लाख 4 हजार 644 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। गेहूं उपार्जन के लिए इस वर्ष प्रदेश में कुल 3627 उपार्जन केंद्र बनाये गये हैं। बीते उपार्जन वर्ष 2025-26 में 15 लाख 44 हजार 55 किसानों ने गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन कराया था। इस उपार्जन वर्ष के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,625 रूपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। मोहन यादव सरकार ने गेहूँ खरीदी के लक्ष्य को 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। समर्थन मूल्य पर निर्बाध खरीदी, स्लॉट अवधि बढ़ाने और सप्ताह में छह दिन उपार्जन सुनिश्चित करने जैसे कदमों से मध्य प्रदेश गेहूँ उत्पादन और खरीदी में देश में अग्रणी बना। इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिला और फसल बिक्री में पारदर्शिता बढ़ी।

सीएम ने किसानों का मन मोहा - मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की किसान-केंद्रित नीतियां व्यावहारिक और दूरदर्शी हैं। भावांतर योजना का विस्तार कर सोयाबीन के बाद सरसों को शामिल किया गया जबकि उड़द और मूंगफली पर समर्थन मूल्य के साथ बोनस की घोषणा हुई। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स पर सब्सिडी से किसानों को मूल्य संवर्धन का अवसर मिलेगा। खेती का रकबा 2.50 लाख हेक्टेयर बढ़ाने, तीन नदी जोड़ो परियोजना से 16 लाख हेक्टेयर सिंचाई, माइक्रो इरीगेशन विस्तार, आधुनिक मंडियां, बीज परीक्षण लैब और फसल नुकसान सर्वे के लिए तहसील-स्तरीय मौसम केंद्र जैसी रोडमैप ने किसानों का मन मोह लिया है। इसके अलावा निः शुल्क मृदा परीक्षण, गुणवत्तापूर्ण बीज और खाद की उपलब्धता, 24 घंटे बिजली, शून्य ब्याज दर पर फसल ऋण, भावांतर योजना जैसे कार्यक्रमों को समर्थन दे रही है, जिसमें बाजार मूल्य और एमएसपी के बीच के अंतर की भरपाई की जाती है जिससे किसान परिवारों तक सीधा लाभ पहुँच रहा है।

फसलों पर बोनस, भूमि अधिग्रहण पर ऐतिहासिक फैसला

किसान कल्याण वर्ष के तहत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के अधिग्रहण पर बाजार दर का चार गुना मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। यह निर्णय विकास कार्यों और किसानों के हितों के बीच संतुलन बनाते हुए किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर रहा है। उड़द पर समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 600 रु प्रति क्विंटल बोनस दिया जा रहा है। सरसों के लिए भावांतर योजना का विस्तार हुआ है। आपदा प्रभावित किसानों को राहत पैकेज के भी सरकार द्वारा वितरित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री का मिशन किसान कल्याण

2026 को कृषि कल्याण वर्ष घोषित कर राज्य सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने, उन्हें आर्थिक सुरक्षा देने और आधुनिक कृषि की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों के उत्थान को अपनी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। डबल इंजन सरकार प्रयासों से वर्ष 2026 मध्यप्रदेश के लाखों किसानों के लिए एक नई उम्मीद की किरण साबित हो रहा है, जहां अनेक योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं।

किसानों के प्रति संवेदनशील 'मोहन' - मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव किसानों के हितों के प्रति संवेदनशील हैं। किसानों के हितों में लिए जा रहे अनेक निर्णय न केवल किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, बल्कि प्रदेश सरकार की किसान कल्याण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का भी प्रतीक भी बन रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के विजन से मध्यप्रदेश में कृषि विकास योजनाएं तेजी से लागू हो रही हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार योजनाओं की पहुँच परिवारों तक पहुंचाने पर जोर दे रही है। ट्रैक्टर रैली, कृषि प्रदर्शनियों और किसान सम्मेलनों के माध्यम से मोहन सरकार किसानों से सीधा संवाद कर रही है। कैबिनेट ने किसान कल्याण से जुड़ी हजारों करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी दी है।

निर्भरता से आत्मनिर्भरता की यात्रा - कृषक मित्र योजना के तहत 90 प्रतिशत सब्सिडी पर सोलर सिंचाई पंप वितरित किए गए हैं जिससे किसान बिजली पर निर्भरता कम कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, उद्यानिकी और तीसरी फसल को प्रोत्साहन देकर कृषि आय विविधीकरण और जैविक खेती पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मध्यप्रदेश देश का इकलौता राज्य है जहां किसानों को 5 रुपये में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉली और भूसे की मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं। सरकार की किसान केंद्रित नीतियों एक प्रभाव से प्रदेश में दुध संग्रहण भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश की कृषि वृद्धि दर 16व तक पहुंचने में इन सभी प्रयासों का महत्वपूर्ण योगदान है।

देश के विकास में देंगे योगदान - मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का मानना है कि किसानों की आमदनी बढ़ाए बिना प्रदेश का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। प्रत्यक्ष लाभ, उचित मूल्य, आधुनिक सिंचाई, विविधीकरण और आपदा राहत के माध्यम से केन्द्र और राज्य सरकार अन्नदाताओं के हर सुख-दुःख में उनके साथ खड़ी है। ये उपलब्धियां न केवल किसानों को सशक्त बना रही हैं, बल्कि मध्यप्रदेश को कृषि प्रधान राज्य के रूप में नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का यह दृष्टिकोण न केवल मध्यप्रदेश को कृषि प्रधान राज्य के रूप में स्थापित करेगा, बल्कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाकर देश के विकास में अपना योगदान देगा। (यह लेखक के अपने विचार हैं)

परीक्षा प्रणाली की अव्यवस्था में फंसते छात्र और टूटता भरोसा

(सुरेश सेठ)

सवाल है कि सरकार ने एक देश, एक परीक्षा की नीति के तहत राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का गठन क्या सोचकर किया था। लाखों विद्यार्थी भाग्य आजमाने के लिए परीक्षाओं में बैठें और प्रश्नपत्र लीक हो जाए, तो इसे क्या कहेंगे। हम सामान्य या असाधारण परिस्थिति का सामना करते हुए जीवन भर परीक्षा देते हैं। मगर इस समय जो चुनौती देश के नौनिहालों के सामने खड़ी हो गई है, वह कहीं अधिक बड़ी है। भरपूर मेहनत करने के बाद जब वे डॉक्टर बनने का सपना साकार करना चाहते हैं, तो उनकी उम्मीदें टूट जाती हैं। इस बार भी यही हुआ। सीबीएसई की 'ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग' में जो शिकायतें आईं, वह सबके सामने है।

नीट के प्रश्नपत्र लीक होने का मामला सुर्खियों में छाया रहा। देश की परीक्षा प्रणाली किस तरह विद्यार्थियों के भविष्य को दांव पर लगा रही है, इसे समझा जा सकता है। पिछले दिनों कुछ विद्यार्थियों ने इस त्रुटिपूर्ण परीक्षा प्रणाली से निराश होकर आत्महत्या कर ली। ये ऐसे विद्यार्थी थे जो भविष्य में चिकित्सक बनकर मरीजों की सेवा करना चाहते थे। समाज में मानवीयता को जिंदा रखना चाहते थे।आज वे स्वयं परीक्षा प्रणाली के कुचक्र में फंस गए हैं। वे खुद को असहाय महसूस करने लगे हैं। उन्हें लगता है कि रात-दिन इतनी मेहनत करने का क्या लाभ, जहां उनकी मेधा का ठीक से मूल्यांकन ही नहीं होता। नतीजा यह कि वे जीवन से भी हार जाते हैं। सवाल है कि हम देश की भावी पीढ़ी के लिए कैसी व्यवस्था तैयार कर रहे हैं।

कोटा से लेकर दिल्ली के कई इलाकों में देखा जा सकता है कि किस तरह युवा सिविल सेवा परीक्षा और नीट की तैयारी करते हैं। इस तैयारी में उनके माता-पिता की उम्मीदें भी जुड़ी रहती हैं। युवा निरंतर मेहनत करते हैं। वे परीक्षा देने जाते हैं और सभी प्रश्नों को सुलझाकर लौटते हैं, इस आशा के साथ कि अब कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ेंगे। मगर कुछ दिनों बाद पता चलता है कि प्रश्नपत्र लीक हो गया है। ऐसे में उनकी सारी आकांक्षाओं पर पानी फिर जाता है।

इस बार नीट के मामले में यही हुआ। इस घटना ने लाखों नौजवानों को निराशा के दलदल में धकेल दिया। यह अजीब बात है कि देश में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के गठन के बावजूद सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं संपन्न नहीं हो रहीं। इस व्यवस्था में भी भ्रष्टाचार का दीमक लग गया।

एनटीए की स्थापना से उम्मीद बनी थी कि विद्यार्थी महत्त्वपूर्ण परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर अपनी पसंद के कॉलेजों और विषयों में दाखिला लेंगे। मगर वास्तविक स्थिति सबके सामने है।

सवाल है कि सरकार ने एक देश, एक परीक्षा की नीति के तहत राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का गठन क्या सोचकर किया था। लाखों विद्यार्थी भाग्य आजमाने के लिए परीक्षाओं में बैठें और प्रश्नपत्र लीक हो जाए, तो इसे क्या कहेंगे। यह कितनी बड़ी त्रासदी है कि विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे नतीजे का, अपने स्वर्णिम भविष्य का और उन्हें मिली निराशा। अब उन्हें दोबारा परीक्षा देनी होगी। ऐसा ही वर्ष 2024 में भी हुआ था, तब भी लाखों विद्यार्थी निराश हुए थे।

कोटा से लेकर दिल्ली के कई इलाकों में देखा जा सकता है कि किस तरह युवा सिविल सेवा परीक्षा और नीट की तैयारी करते हैं। इस तैयारी में उनके माता-पिता की उम्मीदें भी जुड़ी रहती हैं। युवा निरंतर मेहनत करते हैं। वे परीक्षा देने जाते हैं और सभी प्रश्नों को सुलझाकर लौटते हैं, इस आशा के साथ कि अब कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ेंगे।

प्रश्नपत्र लीक होने पर नीट यूजी 2026 को रद्द किया जाना कोई साधारण घटना नहीं। दोबारा परीक्षा लेने का निर्णय जरूर किया गया, लेकिन इससे विद्यार्थियों पर नाहक ही मानसिक दबाव बढ़ा है। जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा दे दी थी, उन्हें मालूम है कि उन्होंने पिछली बार कितनी मेहनत से तैयारी की थी।

अगर दोबारा परीक्षा के दौरान कोई सवाल हल नहीं कर पाए या पिछड़ गए, तब क्या होगा? ऐसे में विद्यार्थियों की मन-स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं कि वे दोबारा उसी क्षमता से परीक्षा दे पाएं। आज भी यह सवाल अपनी जगह कायम है कि आखिर वे कौन-सी खामियां थीं, जिनकी वजह से प्रश्नपत्र लीक हो गए। ये प्रश्नपत्र जयपुर से लेकर लातूर तक बिके। इतनी चाक-चौबंद व्यवस्था से प्रश्नपत्र बाहर निकल गए, तो शिक्षा व्यवस्था संभालने वालों की जवाबदेही तय होनी चाहिए।

बचपन को श्रम नहीं, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान का अधिकार मिलें

(ललित गर्ग)

विशेष रूप से डिजिटल युग में तकनीक का उपयोग बाल श्रम उन्मूलन के लिए किया जा सकता है। प्रत्येक उद्योग और आपूर्ति श्रृंखला की पारदर्शी निगरानी, बाल श्रम शिकायतों के लिए ऑनलाइन पोर्टल, त्वरित कार्रवाई तंत्र और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी प्रणालियां विकसित की जा सकती हैं।

हर वर्ष 12 जून को मनाया जाने वाला बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस केवल एक औपचारिक दिवस नहीं, बल्कि मानवता के अंतःकरण को झकझोरने वाला अवसर है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि दुनिया का कोई भी बच्चा मजदूर बनने के लिए पैदा नहीं होता। उसके हाथों में औजार, ईंट, बर्तन, हथौड़े, कूड़े की बोरी या कारखानों की मशीनें नहीं, बल्कि किताबें, खिलौने, रंग, सुनहले सपने और संभावनाएं होनी चाहिए। बचपन जीवन का वह स्वर्णिम काल है जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व, संस्कार, शिक्षा और भविष्य की नींव रखी जाती है। यदि यही काल श्रम, शोषण और अभाव की भट्ठी में झोंक दिया जाए तो केवल एक बच्चे का नहीं, पूरे समाज और राष्ट्र का भविष्य अंधकारमय हो जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन- आईअलओ द्वारा 2002 में शुरू किए गए इस दिवस का उद्देश्य बाल श्रम की भयावहता के प्रति वैश्विक चेतना जगाना और इसके उन्मूलन के लिए सामूहिक प्रयासों को गति देना है। वर्ष 2026 में भी यह दिवस ऐसे समय पर आ रहा है जब दुनिया तकनीकी विकास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आर्थिक प्रगति के नए आयाम छू रही है, लेकिन दूसरी ओर करोड़ों बच्चे आज भी शिक्षा और बचपन के अधिकार से वंचित हैं। यह विडम्बना मानव सभ्यता के सामने एक गंभीर प्रश्नचिह्न है। जब हम किसी ढाबे, होटल, चाय की दुकान, कारखाने, गैरेज, ईंट-भट्टे, खेत या ट्रैफिक सिग्नल पर किसी मासूम बच्चे को कठिन श्रम करते देखते हैं, तब अक्सर हमारी संवेदना कुछ क्षणों के लिए जागती है और फिर हम अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि कब तक हम इस पीड़ा को सामान्य मानते रहेंगे? क्या हम उस बचपन की चीख नहीं सुन पा रहे जो अपने अधिकारों से वंचित होकर मजदूरी के अंधेरे में खो रहा है?

आज भी विश्व में करोड़ों बच्चे किसी न किसी रूप में बाल श्रम में संलग्न हैं। इनमें से बड़ी संख्या खतरनाक परिस्थितियों में काम करती है, जहां उनका शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास बाधित होता है। गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता, विस्थापन, तस्करी, युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं और कमजोर सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाएं बाल श्रम की प्रमुख वजहें हैं। परिवार की आर्थिक विवशताएं बच्चों को स्कूल की बजाय काम की दुनिया में धकेल देती हैं। लेकिन गरीबी का समाधान बच्चों से काम कराना नहीं, बल्कि परिवारों को सम्मानजनक रोजगार और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। बाल श्रम केवल आर्थिक समस्या नहीं है; यह मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। यह बच्चों से उनका बचपन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद, आत्मविश्वास और भविष्य छीन लेता है। जो बच्चा विद्यालय में होना चाहिए, वह यदि कारखाने में है, तो यह केवल उस बच्चे की नहीं, पूरे समाज की विफलता है। बाल श्रम गरीबी का चक्र भी बनाए रखता है, क्योंकि अशिक्षित बच्चा बड़ा होकर कम आय वाले कार्यों तक सीमित रह जाता है और अगली पीढ़ी भी उसी अभाव में जीने को मजबूर होती है।

आज भी विश्व में करोड़ों बच्चे किसी न किसी रूप में बाल श्रम में संलग्न हैं। इनमें से बड़ी संख्या खतरनाक परिस्थितियों में काम करती है, जहां उनका शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास बाधित होता है। गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता, विस्थापन, तस्करी, युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं और कमजोर सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाएं बाल श्रम की प्रमुख वजहें हैं। परिवार की आर्थिक विवशताएं बच्चों को स्कूल की बजाय काम की दुनिया में धकेल देती हैं। लेकिन गरीबी का समाधान बच्चों से काम कराना नहीं, बल्कि परिवारों को सम्मानजनक रोजगार और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

भारत सहित अनेक देशों में बाल श्रम रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईअलओ के कन्वेंशन 138 और कन्वेंशन 182 न्यूनतम कार्य आयु और बाल श्रम के सबसे खतरनाक रूपों पर रोक लगाने के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करते हैं। भारत में भी बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम तथा शिक्षा का अधिकार कानून मौजूद हैं। लेकिन कानूनों की प्रभावशीलता उनके कठोर और ईमानदार क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। कई बार कानूनी प्रावधान होने के बावजूद बाल श्रम छिपे हुए रूपों में जारी रहता है। आज आवश्यकता केवल कानून बनाने की नहीं, बल्कि उन्हें सामाजिक आंदोलन का स्वरूप देने की है। बाल श्रम को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक जन-जागरण अभियान चलाए जाने चाहिए। विद्यालयों, धार्मिक संस्थाओं, सामाजिक संगठनों, मीडिया, उद्योग जगत और नागरिक समाज को इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। जिस प्रकार पर्यावरण संरक्षण और महिला अधिकारों को लेकर वैश्विक चेतना विकसित हुई है, उसी प्रकार बाल अधिकारों के लिए भी विश्वव्यापी जनमत तैयार करना होगा। कैसा विरोधाभास है कि हमारा समाज, सरकार और राजनीतिज्ञ बच्चों को देश का भविष्य मानते नहीं थकते लेकिन क्या इस उम्र के लगभग 25 से 30 करोड़ बच्चों से बाल मजदूरी के जरिए उनका बचपन और उनसे पढने का अधिकार छीनने का यह सुनियोजित षड्यंत्र नहीं लगता? मिसाल के तौर पर एक कानून बनाकर हमने बच्चों से उनका बचपन छिनने की कुचेष्टा की है। इस कानून में हमने यदि पारिवारिक कामधंधा या रोजगार है तो 4 से 14 की उम्र के बच्चों से कानूनन काम कराया जा सकता है और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह कैसी विडम्बना है कि जब इस उम्र के बच्चों को स्कूल में होना चाहिए, खानदानी व्यवसाय के नाम पर एक पूरी पीढ़ी को शिक्षा, खेलकूद और सामान्य बाल्य सुलभ व्यवहार से वंचित किया जा रहा है और हम अपनी पीठ थपथपाए जा रहे हैं। बच्चों को बचपन से ही आत्मनिर्भर बनाने के नाम पर हकीकत में हम उन्हें पैसा कमाकर लाने की मशीन बनाकर अंधकार में धकेल रहे हैं।

बालक उमावि में 30 जून तक प्रवेश जारी, सभी कक्षाओं में बालिकाओं का भी होगा प्रवेश

नारायणपुर। ज्ञान, संस्कार, अनुशासन एवं उत्कृष्टता के संकल्प के साथ बालक उमावि में नव शैक्षणिक सत्र 2026-27 का शुभारंभ किया गया। नव सत्र के प्रथम दिवस पर बड़ी संख्या में विद्यार्थी एवं अभिभावक विद्यालय पहुंचे। विद्यालय परिवार द्वारा पालकों को प्रवेश प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों, विषय चयन तथा विद्यालय की शैक्षणिक एवं सह-शैक्षणिक गतिविधियों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। विद्यालय परिसर में उत्साहपूर्ण वातावरण के बीच निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, नवीन प्रवेश एवं अध्ययन संबंधी प्रक्रियाएं प्रारंभ की गई। प्राचार्य मनोज बागड़े ने बताया कि विद्यालय में नवीन प्रवेश प्रक्रिया 30 जून 2026 तक संचालित रहेगी। उन्होंने क्षेत्र के समस्त पालकों से अपील की कि वे अपने बच्चों का प्रवेश निर्धारित समय-सीमा के भीतर अवश्य कराएं। प्रवेश के इच्छुक पालक विद्यालय में संबंधित कक्षा शिक्षक से संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हुए प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर सकते है। उन्होंने कहा कि समय पर प्रवेश से विद्यार्थियों को शैक्षणिक गतिविधियों का पूरा लाभ प्राप्त होगा तथा उनकी पढ़ाई सुचारु रूप से संचालित हो सकेगी। विद्यालय की महत्वपूर्ण पहल का उल्लेख करते हुए प्राचार्य ने बताया कि गत शैक्षणिक सत्र से विद्यालय में बालिकाओं को भी प्रवेश दिया जा रहा है। इस पहल को क्षेत्र के अभिभावकों का सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुआ है। नव शैक्षणिक सत्र 2026-27 में भी सभी कक्षाओं में बालिकाओं के प्रवेश लिए जा रहे हैं। उन्होंने अभिभावकों से विशेष रूप से आग्रह किया कि वे अपनी बेटियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित एवं अनुशासित वातावरण तथा बेहतर शैक्षणिक अवसरों का लाभ दिलाने के लिए विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। बेटी पढ़ेगी, तभी समाज आगे बढ़ेगा की भावना को आत्मसात करते हुए विद्यालय बालिका शिक्षा को विशेष प्रोत्साहन दे रहा है। विद्यालय प्रशासन का विश्वास है कि शिक्षित एवं सशक्त बेटियां समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अंत में विद्यालय परिवार ने सभी विद्यार्थियों एवं अभिभावकों का हार्दिक स्वागत करते हुए क्षेत्र के अधिकाधिक विद्यार्थियों एवं बालिकाओं से विद्यालय में प्रवेश लेकर अपने उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में सहभागी बनने का आह्वान किया।

बिजली दर वृद्धि के विरोध में कांग्रेस का विद्युत कार्यालय घेराव, पुलिस से हुई झूमाझटकी

कोण्डागांव। बिजली दरों में बढ़ोतरी के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी कोण्डागांव ने बुधवार को विद्युत विभाग कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस एवं प्रशासन ने विद्युत विभाग कार्यालय परिसर के आसपास कड़े सुरक्षा इंतजाम किए थे। न्यायालय कार्यालय और भाजपा कार्यालय दोनों ओर से बैरिकेडिंग कर रास्तों को बंद कर दिया गया था, ताकि प्रदर्शनकारी कार्यालय परिसर तक न पहुंच सकें। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी प्रदर्शन में शामिल हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यालय की ओर लगाए गए बैरिकेड को हटाने और आगे बढ़ने का प्रयास कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की झूमाझटकी की स्थिति भी बनी। हालांकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने घरेलू, गैर-घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों के लिए बिजली दरों में 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट तक की वृद्धि कर आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला है। विद्युत कार्यालय घेराव के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता शहर के बस स्टैंड पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का पुतला दहन करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने समय रहते हस्तक्षेप कर पुतला दहन नहीं होने दिया। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष रवि घोष ने कहा कि बिजली दर वृद्धि, किसानों को डीजल और अन्य कृषि आवश्यकताओं की उपलब्धता में हो रही समस्याओं के खिलाफ कांग्रेस द्वारा यह आंदोलन किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को घंटों लाइन में लगकर डीजल लेना पड़ रहा है और सरकार उनकी समस्याओं के समाधान में विफल साबित हो रही है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर आगे भी आंदोलन जारी रहेगा।

जिले में बाढ़ आपदा प्रबंधन हेतु नियंत्रण कक्ष स्थापित, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति सहित हेल्पलाइन नंबर्स जारी

जगदलपुर। जिले में आगामी मानसून सीजन के दौरान बाढ़ आपदा प्रबंधन सहित आम जनता की सुरक्षा और आपातकालीन स्थितियों में तुरंत सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से जिला स्तर और तहसील कार्यालयों के अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। साथ ही उक्त बाढ़ नियंत्रण कक्ष हेतु नोडल और सहायक नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। जिसके तहत कलेक्टोरेट जगदलपुर में जिला स्तरीय बाढ़ आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष हेतु डिप्टी कलेक्टर हीरा गवर्ना को नोडल अधिकारी और अधीक्षक भू-अभिलेख मोहनलाल भारद्वाज को सहायक नोडल अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है। इसी तरह जिले के अंतर्गत सभी तहसील स्तर में भी बाढ़ आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं और संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिसके तहत तोकापाल तहसील में नायब तहसीलदार गजेन्द्र सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिनसे संपर्क किया जा सकता है। बकावण्ड तहसील में नायब तहसीलदार सुनील कुमार ध्रुव और लोहण्डीगुड़ा तहसील में नायब तहसीलदार खुशबू नेताम को नोडल अधिकारी बनाया गया है। वहीं जगदलपुर तहसील कार्यालय के अंतर्गत तहसीलदार राहुल कुमार गुप्ता को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिनकी सहायता के लिए नायब तहसीलदार डोमनलाल सहारे और लखीराम पाण्डे को सहायक नोडल अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह बास्तानार तहसील में राजस्व निरीक्षक राजेश कुमार तिवारी को नोडल और पवन कुमार नेताम को सहायक नोडल अधिकारी का दायित्व मिला है। दरभा तहसील में नायब तहसीलदार जयंत कुमार, बस्तर तहसील में फूलबती भूआर्य और नानगुर तहसील में नायब तहसीलदार रोहन बिसी को नोडल अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त भानपुरी तहसील में नायब तहसीलदार चन्द्रकुमार साहू को नोडल अधिकारी तथा राजस्व निरीक्षक मुकेश कोर्राम को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि करपावण्ड तहसील में राजस्व निरीक्षक देवेन्द्र श्रीवास को नोडल अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे बाढ़ या जलभराव जैसी किसी भी आपातकालीन स्थिति में सहायता हेतु अपने नजदीकी क्षेत्र के इन संबंधित दूरभाष और मोबाइल नंबरों पर तुरंत संपर्क कर सकते हैं।

जिला नारायणपुर के पत्रकारों ने पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर एकदिवसीय धरना प्रदर्शन किया

नारायणपुर। नारायणपुर के हृदय स्थल जय स्तंभ चौक पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन नारायणपुर जिले के सभी पत्रकारों ने किया। मुख्य मांग छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द से जल्द लागू किया जाए विषय था। यह धरना प्रदर्शन सुबह 10:00 बजे प्रारंभ किया गया एवं 11:30 बजे कलेक्टर नम्रता जैन को ज्ञापन मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के नाम दिया गया। उक्त धरना प्रदर्शन पर पत्रकार साथियों ने एक जूटता का परिचय देते हुए जबरदस्त हुंकार भरी पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करो, पत्रकारों की चिंता करो, नारायणपुर पत्रकार जिंदाबाद जिंदाबाद जैसे नारों से नारायणपुर का हृदय स्थल जय स्तंभ चौक (आज का धरना स्थल) गूंजायमान हो गया था। धरना प्रदर्शन के इस कार्यक्रम में पत्रकार सुनील सिंह राठौर, मोहम्मद इमरान, अभिषेक बैनर्जी, श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ के अध्यक्ष संजय राय, छत्तीसगढ़ जर्नलिज्म यूनियन के अध्यक्ष पुष्पेंद्र ठाकुर, साथ ही अन्य पत्रकार साथी प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व पोर्टल से संबंधित पत्रकार साथी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे एवं अपना अपना परिचय के पश्चात धरना प्रदर्शन में पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर अपने विचार प्रकट करते हुए शासन से उक्त कानून को जल्द से जल्द क्रियान्वित कर पत्रकारों की अत्यंत आवश्यक मांग हेतु आवाज बुलंद की। पत्रकार सुनील सिंह राठौर ने कहा पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए पत्रकार सुरक्षा कानूनलागू करने की हम सभी पत्रकार मांग करते है। हम पत्रकार साथी इस धरना प्रदर्शन में सम्मिलित होकर मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के नाम ज्ञापन कलेक्टर नम्रता जैन को सौंप कर अप पत्रकार सुरक्षा कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग करते हैं। राठौर ने आगे कहा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए ताकि पत्रकार बिना किसी भय के अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके। यह कानून एक ऐसा प्रस्तावित या लागू किया गया कानून है जो पत्रकारों को उनके पेशेवर कार्य के दौरान होने वाली हिंसा, अनुचित मुकदमों और उत्पीड़न से बचाता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना और पत्रकारों को बिना किसी भय या दबाव के स्वतंत्र रूप से काम करने का माहौल प्रदान करता है। मोहम्मद इमरान (छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ प्रदेश सचिव) ने अपने उदबोधन में कहा हमारा मुख्य मुद्दा तो पत्रकार सुरक्षा कानून ही है। आज लोगों की मानसिकता पत्रकारों पर टिप्पणी करते हुए कहते है कि यह पत्रकार कांग्रेस गुट से है, ये पत्रकार भाजपा प्रवृत्ति का है। जबकी पत्रकार स्वतंत्र होता है वह सभी के लिए एक सेतु का काम करता है कभी जनमानस के लिए, तो कभी शासन तो कभी प्रशासन के लिए कार्य करता है। डॉ अभिषेक बैनर्जी (संभागीय प्रदेशअध्यक्ष छत्तीसगढ़ जर्नलिज्म यूनियन) ने अपने वक्तव्य में कहा विगत वर्षों में जनहित से जुड़े समाचारों के प्रकाशन के कारण पत्रकारों के विरुद्ध झूठी एवं दुर्भावना पूर्ण शिकायतें दर्ज होने तथा उन्हें अनावश्यक दबाव और प्रताड़ना का सामना करने की घटनाएं बढ़ी है। इससे असुरक्षा का वातावरण बन रहा है, कई मामले तो ऐसे भी देखने में आए हैं जिसमें थानों में बिना जांच के ही सीधे अपराध दर्ज कर दिए जाते हैं।

आदिवासियों की बेदखली के विरोध में सीपीआई का धरना, मानसून में घर तोड़ने पर लगाई रोक की मांग

कोण्डागांव। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) ने चौपाटी मैदान में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन कर आदिवासी परिवारों के घरों को तोड़े जाने और खेती की जमीनों से बेदखल किए जाने के खिलाफ आवाज बुलंद की। धरना के बाद राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि वन एवं राजस्व भूमि पर वर्षों से निवास और खेती कर रहे आदिवासी परिवारों को मानसून के ठीक पहले बेदखल किया जा रहा है, जिससे महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो रहे हैं। पार्टी ने इस कार्रवाई को अमानवीय, असंवैधानिक और आदिवासी विरोधी बताया। धरना को संबोधित करते हुए सीपीआई के संभागीय संयोजक तिलक पांडे ने कहा कि, कई ऐसे परिवार हैं जिन्हें वन अधिकार पट्टा प्राप्त है और कई परिवारों के पट्टों की प्रक्रिया चल रही है, इसके बावजूद वन विभाग और प्रशासन द्वारा बिना पूर्व सूचना मकान तोड़े जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चिलियाबेड़ा सहित कई क्षेत्रों में प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान लोगों के घरों में रखा अनाज, नकदी और बच्चों के शैक्षणिक दस्तावेज भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पांडे ने कहा कि अनेक परिवारों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिससे ग्रामीणों में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। सीपीआई ने मांग की है कि, मानसून के दौरान आदिवासियों के घरों को तोड़ने और खेतों से बेदखल करने की कार्रवाई तत्काल बंद की जाए, वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत पात्र परिवारों को पट्टे प्रदान किए जाएं तथा प्रभावित परिवारों को राहत और पुनर्वास उपलब्ध कराया जाए। पार्टी ने यह भी सवाल उठाया कि जिन आदिवासियों को पहले वन भूमि पर बसने और खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, आज उन्हीं को बेघर क्यों किया जा रहा है। सीपीआई ने चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं रुकी तो इस मुद्दे को राज्य स्तर पर उठाकर व्यापक जनआंदोलन चलाया जाएगा।

एएम-एनएस इंडिया किरंदुल की सीएसआर पहल फुलपाड़ ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन

किरंदुल। ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुलभ बनाने और बेहतर चिकित्सा सुविधा पहुंचाने के अपने संकल्प को दोहराते हुए, आर्सेलरमित्तल निप्पन स्टील इंडिया (एएम-एनएस इंडिया) किरंदुल द्वारा ग्राम पंचायत फुलपाड़ में एक वृहद स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योजना के तहत आयोजित इस शिविर में स्थानीय ग्रामीणों ने भारी उत्साह दिखाया, जहां अनुभवी चिकित्सा टीम द्वारा कुल 64 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस एक दिवसीय शिविर का मुख्य उद्देश्य मौसमी बीमारियों की रोकथाम और ग्रामीण आबादी में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना था। शिविर के दौरान कुल 55 मरीजों का गहन उपचार किया गया और उन्हें आवश्यक निशुल्क दवाइयां वितरित की गईं। स्वास्थ्य जांच के दायरे को विस्तृत करते हुए आधुनिक पैथोलॉजिकल सुविधाओं का भी लाभ दिया गया, जिसके अंतर्गत 35 ग्रामीणों के रक्त के नमूने लेकर उनकी बीपी-शुगर और मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों की जांच मौके पर ही की गई। रिपोर्ट के आधार पर मरीजों को उचित खान-पान और जीवनशैली के संबंध में डॉक्टरी सलाह भी दी गई। इस स्वास्थ्य अभियान को सफल बनाने में स्थानीय पंचायत प्रशासन और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का अभूतपूर्व योगदान रहा। ग्राम पंचायत फुलपाड़ के सरपंच, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और समर्पित मितानिनों ने न केवल ग्रामीणों को शिविर तक लाने में मदद की, बल्कि स्वास्थ्य टीम के साथ समन्वय कर पूरी व्यवस्था का संचालन सुचारू बनाया। सरपंच ने कंपनी के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि पहुंचविहीन क्षेत्रों में इस प्रकार के शिविर न केवल बीमारियों की पहचान करने में मददगार हैं, बल्कि इससे ग्रामीणों के आर्थिक बोझ में भी कमी आती है। एएम-एनएस इंडिया किरंदुल प्रबंधन ने इस अवसर पर कहा कि कंपनी स्थानीय समुदायों के सर्वांगीण विकास और विशेषकर स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आने वाले समय में दंतेवाड़ा जिले के अन्य दूरस्थ पंचायतों में भी इसी तरह के विशिष्ट स्वास्थ्य शिविरों की श्रृंखला आयोजित की जाएगी ताकि कोई भी ग्रामीण बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं से वंचित न रहे।

ग्राम पंचायतों में 24 जून को विशेष ग्राम सभाओं का होगा आयोजन, आवास प्लस 2.0 की स्थायी प्रतीक्षा सूची पर होगी चर्चा

नारायणपुर। छत्तीसढ़ शासन के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राज्य की ग्रामीण प्रगति और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। आगामी 24 जून को प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन ग्राम सभाओं का मुख्य उददेश्य ग्रामीण विकास योजनाओं को धरातल पर मजबूत करना और आम जनता की भागीदारी को बढ़ाना है।

इन सभाओं में मुख्य रूप से आवास प्लस 2.0 की स्थायी प्रतीक्षा सूची को लेकर विस्तृत चर्चा की जाएगी। दावे और आपत्तियों का निराकरण पात्र हितग्राहियों की प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी। इसके साथ ही, सूची को लेकर प्राप्त होने वाले दावों और आपत्तियों का नियमानुसार निराकरण भी किया जाएगा ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे। ग्रामीण विकास एवं जनभागीदारी सभाओं के दौरान विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और ग्रामीणों की सक्रिय जनभागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत जिला नारायणपुर में आवास प्लस 2.0 के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के 10465 लोगो का सर्वे का कार्य किया गया है जिसके अंतर्गत जनपद पंचायत नारायणपुर में 8818 एवं जनपद पंचायत ओरछा में 1647 है। विभाग द्वारा सभी ग्रामीणजनों से अपील की गई है कि वे 24 जून को आयोजित होने वाली इस ग्राम सभा में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित रहें।

मंत्री केदार कश्यप ने किया बस्तर कृत कार्यशाला का उद्घाटन, स्थानीय कला को मिलेगा नया बाजार

कोण्डागांव। मंत्री केदार कश्यप ने झिटकू-मिटकू संस्था द्वारा निर्मित बस्तर कृत नवीन कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बस्तर की पारंपरिक कला एवं शिल्प को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तैयार की गई कार्यशाला का अवलोकन भी किया गया।

कार्यशाला परिसर में बस्तर आर्ट के माध्यम से निर्मित बेल मेटल आर्ट, डोकरा आर्ट तथा अन्य स्थानीय हस्तशिल्प कलाकृतियों की गैलरी भी स्थापित की गई है। बस्तर कृत के शुभारंभ से स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन एवं विपणन के लिए बेहतर मंच उपलब्ध होगा। इससे बस्तर की पारंपरिक कला को नई पहचान मिलने के साथ-साथ कलाकारों की आजीविका और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

प्रवेश चयन परीक्षा परिणाम जारी : चयनित विद्यार्थियों को 30 जून तक लेना होगा प्रवेश

नारायणपुर। सत्र 2026-27 के अंतर्गत जिला नारायणपुर में संचालित विशिष्ट 500-500 सीटर शासकीय कन्या शिक्षा परिसर गरांजी एवं शासकीय बालक बुनियादी आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गरांजी में कक्षा 6वीं, 9वीं एवं 11वीं की रिक्त सीटों पर नवीन प्रवेश के लिए आयोजित प्रवेश चयन परीक्षा का परिणाम एवं चयन सूची 16 जून को जारी कर दी गई है। प्रवेश चयन परीक्षा का आयोजन 10 जून को किया गया था। चयनित छात्र-छात्राएं 17 जून से 30 जून तक विद्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक प्रवेश नहीं लेने वाले विद्यार्थियों की रिक्त सीटों पर प्रतीक्षा सूची से 1 जुलाई से 7 जुलाई तक प्रवेश दिया जाएगा। विद्यालय प्रशासन द्वारा प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची भी जारी की गई है। चयनित विद्यार्थियों को मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी), पासपोर्ट साइज फोटो, अंकसूची, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाते के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड तथा पालक का पासपोर्ट साइज फोटो प्रस्तुत करना होगा। अन्य जिले के विद्यार्थियों को टीसी पर जिला शिक्षा अधिकारी के काउंटर हस्ताक्षर कराना अनिवार्य होगा। विद्यालय प्रबंधन ने चयनित विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों से निर्धारित समयावधि में आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की अपील की है।

जिला अस्पताल कोंडागांव में 18 जून 2026 को नि:शुल्क कैंसर जांच एवं परामर्श शिविर

कोण्डागांव। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जिला कोंडागांव तथा बाल्को मेडिकल सेंटर रायपुर के संयुक्त तत्वावधान में जिला अस्पताल कोंडागांव में निःशुल्क कैंसर जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन गुरूवार को किया जाएगा। शिविर के आयोजन में जिला नोडल अधिकारी गैर संचारी रोग कार्यक्रम डॉ. ममता ठाकुर एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक डॉ भावना मलवार (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। शिविर में स्तन कैंसर की जांच हेतु (मैमोग्राफी) बच्चेदानी के मुंह की कैंसर की जांच हेतु (पेप स्मीयर) तथा मुख कैंसर परीक्षण (ब्रश साइटोलाजी) एवं विभिन्न प्रकार के कैंसरों की जांच अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से की जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ आर. के. चतुर्वेदी ने बताया कि कैंसर के प्रारंभिक लक्षणों की समय पर पहचान एवं जांच से उपचार की सफलता की संभावना काफी बढ़ जाती है। उन्होंने कैंसर के संभावित लक्षणों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि स्तन में गांठ या असामान्य उभार मुंह में घाव या बदलाव आवाज में भारीपन लगातार खांसी, निगलने में कठिनाई, लंबे समय तक ठीक न होने वाले घाव, त्वचा में बदलाव, बिना कारण वजन कम होना, मल-मूत्र की आदतों में परिवर्तन, महिलाओं में मासिक धर्म चक्र में असामान्य बदलाव तथा पेट के निचले हिस्से में लगातार दर्द जैसे लक्षणों को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने जिले के नागरिकों से अपील की है कि यह जांच शिविर पूर्णतः निःशुल्क है। किसी भी प्रकार के लक्षण अथवा कैंसर संबंधी संदेह होने पर शिविर में पहुंचकर अपनी जांच अवश्य करवाएं तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श प्राप्त करें। स्वास्थ्य विभाग ने जिले के सभी नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में शिविर में उपस्थित होकर इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा का लाभ लेने की अपील की है।

संक्षिप्त समाचार

नीट यूजी 2026 अभ्यर्थियों के लिए सिम्स में 24म7 मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन शुरू

बिलासपुर। नीट यूजी 2026 परीक्षा परिणाम एवं प्रवेश प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों में बढ़ते मानसिक तनाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स), बिलासपुर ने अभ्यर्थियों के लिए 24म7 मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सेवा प्रारंभ की है। चिकित्सा शिक्षा आयुक्त, छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार सिम्स के मनोरोग विभाग के माध्यम से यह विशेष सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे विद्यार्थियों को समय पर मनोवैज्ञानिक परामर्श और भावनात्मक सहयोग मिल सके। सिम्स अधिष्ठाता कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार मोबाइल नंबर 9425502353 को 18 जून 2026 से आगामी दो सप्ताह तक हेल्पलाइन नंबर के रूप में संचालित किया जाएगा। इस दौरान विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम, काउंसिलिंग, प्रवेश प्रक्रिया एवं भविष्य को लेकर होने वाली चिंता, तनाव, घबराहट अथवा अन्य मानसिक समस्याओं के संबंध में विशेषज्ञ चिकित्सकों से मार्गदर्शन प्राप्त होगा।

पशुपालन विभाग की मैदानी संस्थाओं के संचालन समय में बदलाव

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ शासन के पशुधन विकास विभाग द्वारा संचालित मैदानी चिकित्सा संस्थाओं के संचालन समय में संशोधन किया गया है। शासन के आदेशानुसार अब पशु चिकित्सालय, पशु औषधालय, कृत्रिम गर्भाधान केंद्र, कृत्रिम गर्भाधान उपकेंद्र तथा मुख्य ग्राम इकाइयों का संचालन प्रतिदिन सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया जाएगा। संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं, डॉ जीएसएस तंवर ने बताया कि शासन के निर्देशों के अनुसार शासकीय अवकाश के दिनों में भी इन संस्थाओं का संचालन सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया जाएगा, ताकि पशुपालकों को आवश्यक सेवाएं समय पर उपलब्ध हो सकें। पशुधन विकास विभाग ने जिले के सभी पशुपालकों, डेयरी संचालकों, किसानों एवं आम नागरिकों से अपील की है कि वे पशु चिकित्सा एवं संबंधित सेवाओं का लाभ निर्धारित समयावधि में प्राप्त करें। विभाग के अंतर्गत संचालित सभी मैदानी संस्थाएं नए समयानुसार नियमित रूप से कार्य करेंगी।

बिलासपुर यातायात पुलिस की पहलः 1000 से अधिक एनसीसी और स्काउट गाइड कैडेट बने सड़क सुरक्षा के ब्रांड एंबेसडर

बिलासपुर। सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति युवाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से बिलासपुर यातायात पुलिस द्वारा एक विशेष यातायात प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। गुरु घासीदास विद्यालय के रजत जयंती सभा कक्ष में आयोजित इस कार्यशाला में 1000 से अधिक एनसीसी एवं स्काउट गाइड कैडेटों को सड़क सुरक्षा, यातायात नियमों और आधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली की विस्तृत जानकारी दी गई।पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे के पर्यवेक्षण में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा वर्ग में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सड़क दुर्घटनाओं को कम करना था।कार्यशाला के दौरान कैडेटों को आईटीएमएस (इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम), नेक्स्ट जेन एम-परिवहन, पीओएस मशीन तथा बॉडी वॉर्न कैमरा जैसी आधुनिक तकनीकों के माध्यम से यातायात नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन की जानकारी दी गई। साथ ही सड़क सुरक्षा के विभिन्न मानकों एवं नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।यातायात अधिकारियों ने युवाओं को बताया कि सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए खतरनाक स्टंट करना, तेज एवं लापरवाही से वाहन चलाना, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन या ईयरबड्स का उपयोग करना, हेलमेट एवं सीट बेल्ट नहीं लगाना, नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करना तथा मॉडिफाइड साइलेंसर और अमानक लाइटों का उपयोग करना न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकता है।कार्यक्रम में उपस्थित सभी कैडेटों को यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए यातायात पुलिस का ब्रांड एंबेसडर बनाया गया, ताकि वे अपने परिवार, मित्रों और समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य कर सकें।इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे, लोकेश देवा, आशीष शर्मा, देवेश सहित एनसीसी अधिकारी, आर्मी स्टाफ स्काउट-गाइड पदाधिकारी एवं 1000 से अधिक कैडेट उपस्थित रहे।यातायात पुलिस का मानना है कि युवाओं में ट्रैफिक सेंस और सिविक सेंस विकसित कर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। इसी उद्देश्य से शहर के विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक संस्थानों में लगातार जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

डीआरएम कप 2026 का भव्य समापन

सीसीसी कोरबा की टीम बनी विजेता

बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे बिलासपुर मंड़ल के नार्थ-ईस्ट इंस्टीट्यूट बिलासपुर द्वारा रेलवे के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के मध्य आपसी भाईचारा, बेहतर सामंजस्य स्थापित करने एवं उनके मनोरंजन के उद्देश्य से अंतर-विभागीय फ्लडलाइट क्रिकेट प्रतियोगिता डीआरएम कप-2026 का आयोजन दिनांक 22 मई 2026 से एनईआई मैदान में किया गया ।वरिष्ठ मंडल खेल अधिकारी एवं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अनुराग कुमार सिंह के द्वारा इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया था। इस प्रतियोगिता में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल,कंस्ट्रक्शन एवं मुख्यालय की कुल 37 टीमों ने भाग लिया। लीग एवं नॉकआउट आधार पर आयोजित प्रतियोगिता में कुल 84 मैच खेले गए । फ़ाइनल मुकाबला कंस्ट्रक्शन इलेवन एवं सीसीसी कोरबा के टीमों के मध्य खेला गया 7 टॉस जीतकर सीसीसी कोरबा की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 10 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 76 रन बनाए। जवाब में कंस्ट्रक्शन इलेवन की पूरी टीम 48 रनों पर सिमट गई। इस प्रकार सीसीसी कोरबा ने कंस्ट्रक्शन इलेवन को 28 रनों से पराजित कर डीआरएम कप-2026का खिताब अपने नाम किया 7 सीसीसी कोरबा के कप्तान डेविड मंडावी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 ओवर में 10 रन देकर 4 विकेट हासिल किए तथा 7 रन का योगदान दिया, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द फाइनल चुना गया। तीसरे स्थान के मुकाबले में सीनियर डीईई (ओपी) इलेवन ने सीनियर डीएसटीई इलेवन को 5 रनों से हराकर प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया । मैच के अंतिम ओवर में पी.वी. शिवाजी ने

लगातार चार गेंदों पर चार विकेट लेकर टीम को रोमांचक जीत दिलाई और प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किए गए। प्रतियोगिता में बेस्ट गेंदबाज कंस्ट्रक्शन इलेवन के सी दिलीप चंद्रा, बेस्ट बल्लेबाज सीनियर डीएसटीई ङ्गङ्घ के धर्मेन्द्र, बेस्ट क्षेत्ररक्षक सीनियर डीपीओ ङ्गङ्घ के शुभम महतो एवं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सीनियर डीईई (ओपी) के अंजनी कुमार रहे जिन्हे पुरस्कृत किया गया। समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री के. श्रीनिवास राव, , विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी डॉ अंशुमान मिश्रा रहे । समापन समारोह के दौरान अतिथियों के समक्ष नृत्य कला का प्रदर्शन किया गया तथा पूरे मैदान में आतिश-बाजियों की चमक ने दर्शकों का मन मोह लिया। इसके पश्चात अतिथियों द्वारा विजेता एवं उपविजेता टीमों को ट्रॉफी प्रदान की गई। प्रतियोगिता के सफल आयोजन में नार्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरी श्री सी नवीन कुमार , उपाध्यक्ष श्री अमरनाथ सिंह , सह-सचिव श्री संजय कुमार तिवारी , कोषाध्यक्ष श्री बी अनिल कुमार , सह-कोषाध्यक्ष श्री श्रीकांत पाढी , मीडिया प्रभारी श्री हेमंत सिंह परिहार, टूर्नामेंट सचिव श्री दीपक कुमार सुब्बा , टूर्नामेंट सह-सचिव श्री दीपक राजा गुरुंग , आउटडोर सेक्रेटरी श्री टी सन्मुख राव , इनडोर सेक्रेटरी श्री डी मुरलीधर , लाइब्रेरी सेक्रेटरी श्री श्रीराम यादव का योगदान उल्लेखनीय रहा।

वीबी-जीराम जी योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण संपन्न......

बिलासपुर। भारत सरकार एवं राज्य कार्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार वीबी-जीराम जी योजना के संबंध में संभाग स्तरीय दो दिवसीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण का आयोजन जिला पंचायत में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, कोरबा, रायगढ़, सक्ती एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ में पदस्थ कार्यक्रम अधिकारियों (मनरेगा) ने भाग लिया। कार्यशाला में जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप अग्रवाल, सहायक परियोजना अधिकारी श्रीमती अनुराधा शुक्ला, अन्य जिलों के सहायक परियोजना अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी मौजूद थे। कार्यशाला में राज्य कार्यालय से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रतिभागियों को वीबी-

जीराम जी योजना के विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान मनरेगा अंतर्गत कार्यों की प्राथमिकता निर्धारण, पारदर्शिता के साथ क्रियान्वयन, निगरानी व्यवस्था तथा तकनीकी प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों पर विस्तार से प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण में बताया गया कि वीबी-जीराम जी योजना आगामी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी रूप से प्रारंभ की जानी है। इसे ध्यान में रखते हुए योजना की तैयारियों, कार्ययोजना निर्माण एवं समावेशी क्रियान्वयन रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने तथा जन-जन को इससे जोड़ने के उपायों पर भी मार्गदर्शन दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों की समझ और दक्षता का मूल्यांकन करने के लिए पोस्ट असेसमेंट भी आयोजित किया गया।

पशुओं को गलघोटू और एक टंगिया बीमारी से बचाने निःशुल्क टीकाकरण अभियान जारी......

■ पशुपालक कराएं पशुओं का समय पर टीकाकरण, विभाग की अपील

बिलासपुर। पशुपालन विभाग द्वारा जिले में पशुओं के गलघोटू एवं एक टंगिया बीमारी से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य गौवंश एवं भैंसवंशीय पशुओं को वर्षा ऋतु में फैलने वाली घातक संक्रामक बीमारियों गलघोटू (एचएस) तथा एक टंगिया (एचक्यू) से सुरक्षित करना है। गलघोटू से संक्रमित पशुओं में तेज बुखार, गले में सूजन एवं लार टपकने जैसे लक्षण तथा एक टंगिया से संक्रमित पशुओं में मांसपेशियों में सूजन और लंगड़ापन के लक्षण देखने को मिलते है। ये

दोनों बीमारियां पशुओं में उच्च मृत्यु दर का कारण बनती हैं, जिससे पशुपालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इन रोगों की रोकथाम के लिए नियमित टीकाकरण सबसे प्रभावी उपाय माना गया है। अभियान के तहत जिले के सभी विकासखंडों में विभागीय पशु चिकित्सकों एवं पशुधन विकास अधिकारियों द्वारा पात्र पशुओं का निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है। पशुपालन विभाग ने पशुपालकों से अपील की है कि वे अपने सभी पात्र पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाकर उन्हें संक्रामक रोगों से सुरक्षित रखें। संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं बिलासपुर डॉ. जी.एस.एस. तंवर ने जिले के सभी पशुपालकों से अपने निकटतम पशु चिकित्सालय, पशु औषधालय अथवा विभागीय कर्मचारियों से संपर्क कर निःशुल्क एचएस एवं बीक्यू टीकाकरण कराने तथा जनहित के इस अभियान को सफल बनाने में सहयोग करने का आग्रह किया है।

20 जून को जारी होगी पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त

बिलासपुर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के अंतर्गत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की दिशा में 20 जून 2026 को 23वीं किस्त जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से दोपहर 3.45 बजे देशभर के पात्र किसानों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से राशि हस्तांतरित करेंगे। इस अवसर पर बिलासपुर जिले के 99 हजार 906 किसान परिवारों को लगभग 19 करोड़ 98 लाख रुपये की राशि प्राप्त होगी। यह सहायता खरीफ सीजन के दौरान किसानों को बीज, उर्वरक एवं अन्य कृषि आदानों की व्यवस्था करने में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करेगी। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये की सहायता तीन समान किस्तों में प्रदान की जाती है। प्रत्येक चार माह के अंतराल पर 2 हजार रुपये की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। इससे पहले 22वीं किस्त मार्च 2026 में जारी की गई थी। योजना के सफल क्रियान्वयन एवं प्रधानमंत्री के संबोधन के लाइव प्रसारण के लिए कृषि विज्ञान केंद्र, सरकंडा में विशेष व्यवस्था की गई है। यहां जिले के किसान कार्यक्रम से जुड़कर प्रधानमंत्री का संबोधन सुन सकेंगे तथा योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी ई-केवाईसी, एग्रीस्टैक फार्मर्स आईडी, आधार सत्यापन तथा बैंक खाते की जानकारी अद्यतन रखें, ताकि किस्त की राशि प्राप्त करने में किसी प्रकार की समस्या न हो।

यात्री सुविधाओं के उन्नयन हेतु दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे एवं आईआईएम रायपुर के मध्य विचार-विमर्श हुआ

बिलासपुर। दिनांक 17 जून, 2026 को प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर, श्री विजय कुमार के कार्यालय कक्ष में भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), रायपुर के वरिष्ठ प्रतिनिधियों एसोसिएट प्रोफेसर श्री दीप्तिमान बनर्जी एवं श्री अभिजीत बर्मन के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई । बैठक में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे एवं आईआईएम रायपुर के मध्य हाल ही में संपन्न समझौता ज्ञापन (रूम) के अंतर्गत यात्री यातायात, यात्री सुविधा, सेवा गुणवत्ता में सुधार तथा राजस्व संवर्धन से संबंधित अध्ययन कार्यों पर विस्तृत चर्चा की गई । बैठक के दौरान इस बात पर विचार-विमर्श किया गया कि आईआईएम रायपुर किस प्रकार वैज्ञानिक अध्ययन एवं डेटा आधारित विश्लेषण के माध्यम से यात्रियों के आराम, सुविधा तथा यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने में रेलवे की सहायता कर सकता है। संभावित नए यात्री बाजारों की पहचान, नई रेलगाड़ियों की आवश्यकता का आकलन, रेलगाड़ियों के समय निर्धारण एवं परिचालन में सुधार, यात्री सुविधाओं के उन्नयन तथा सेवा गुणवत्ता में सुधार जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा

हुई । आईआईएम रायपुर के प्रतिनिधियों ने बताया कि अध्ययन के अंतर्गत यात्रा पैटर्न, यात्री प्राथमिकताओं, अधिभोग प्रवृत्तियों, क्षेत्रवार मांग तथा विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सुझावों का विश्लेषण किया जाएगा। अध्ययन के आधार पर नई रेल सेवाओं के संचालन, वर्तमान समय-सारिणी के युक्तिकरण तथा यात्रियों की सुविधा बढ़ाने संबंधी सुझाव दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को प्रदान किए जाएंगे । प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक श्री विजय कुमार ने कहा कि यात्रियों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने तथा रेलवे की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रबंधन पद्धतियों एवं विश्लेषणात्मक तकनीकों का उपयोग अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आईआईएम रायपुर के साथ यह सहयोग यात्री-केंद्रित सेवाओं के विकास एवं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की यात्री आय में वृद्धि के लिए उपयोगी सिद्ध होगा । बैठक का समापन अध्ययन को सफलतापूर्वक पूर्ण करने तथा यात्रियों के अनुभव, सुविधा एवं परिचालन दक्षता में सुधार हेतु नवाचारी उपायों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता के साथ हुआ ।

बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध बिलासपुर मंडल में चला विशेष नाका टिकट चेकिंग अभियान

■ 5,646 मामलों में कार्रवाई, 36 लाख रुपये से अधिक की वसूली

बिलासपुर। रेलवे राजस्व की सुरक्षा, यात्रियों में टिकट लेकर यात्रा करने की आदत को प्रोत्साहित करने तथा बिना टिकट एवं अनियमित यात्रा पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर मंडल द्वारा दिनांक 21 मई 2026 से 14 जून 2026 तक विशेष नाका टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। यह अभियान मुख्यालय के निर्देशानुसार वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अनुराग कुमार सिंह के मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण में संचालित किया गया। अभियान के दौरान मंडल के बिलासपुर, चांपा, रायगढ़ सहित सभी प्रमुख स्टेशनों तथा विभिन्न मेल/एक्सप्रेस एवं यात्री ट्रेनों में व्यापक स्तर पर टिकट जांच की गई। इस विशेष अभियान में वाणिज्य विभाग के अधिकारियों, वाणिज्य निरीक्षकों, मुख्य टिकट निरीक्षकों, टिकट जांच कर्मचारियों तथा रेलवे सुरक्षा बल (ऋक्क) के कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए आकस्मिक निरीक्षण एवं सघन टिकट जांच अभियान संचालित किया। इस विशेष अभियान के दौरान कुल 5,646 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 3,667 बिना टिकट यात्रा, 1,814 अनियमित यात्रा 159 बिना बुक किए गए सामान (लगेज) तथा 06 गंदगी फैलाने से संबंधित मामले शामिल हैं। इन मामलों में संबंधित यात्रियों से किराया एवं जुर्माना के रूप में 36 लाख 10 हजार 06 रुपये

की राशि वसूल की गई। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अनुराग कुमार सिंह ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य केवल राजस्व संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि यात्रियों में वैध टिकट के साथ यात्रा करने के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा रेलवे नियमों के पालन को सुनिश्चित करना भी है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से बिना टिकट एवं अनियमित यात्रा पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ है, रेलवे राजस्व में वृद्धि हुई है तथा वैध टिकटधारी यात्रियों को अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित एवं सुविधाजनक यात्रा वातावरण उपलब्ध कराने में सहायता मिली है। रेलवे प्रशासन यात्रियों से अपील करता है कि वे यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व उचित एवं वैध टिकट अवश्य प्राप्त करें तथा अपने सामान की नियमानुसार बुकिंग कराएं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा यात्रियों के हित एवं रेलवे नियमों के प्रभावी अनुपालन हेतु भविष्य में भी इस प्रकार के विशेष टिकट जांच अभियान नियमित रूप से चलाए जाते रहेंगे।

200 रुपये के बिल को लेकर अस्पताल में बवाल:युवकों ने चाकू लहराकर दी धमकी

बिलासपुर। तिफरा स्थित न्यू जनता अस्पताल में महज 200 रुपये के बिल भुगतान को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि इलाज कराने पहुंचे युवकों ने अस्पताल परिसर में हंगामा खड़ा कर दिया। आरोप है कि युवकों ने चाकू लहराते हुए अस्पताल कर्मचारियों और सुरक्षा गार्ड को धमकाया तथा परिसर में तोड़फोड़ भी की। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, बोरी फैक्ट्री के पास तिफरा निवासी नारायण मिश्रा, जो न्यू जनता अस्पताल में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत हैं, ने सिरगिट्टी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में बताया गया है कि 15 जून की रात वह अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात थे। रात करीब 12:20 बजे दो युवक इलाज कराने अस्पताल पहुंचे थे। उपचार के बाद बिल भुगतान को लेकर उनका अस्पताल के कर्मचारियों वाशु और प्रियंका से विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते बहस बढ़ने लगी और अस्पताल परिसर में तनावपूर्ण स्थिति निर्मित हो गई। स्थिति को शांत कराने के लिए सुरक्षा गार्ड नारायण मिश्रा ने दोनों युवकों को समझाने और विवाद बंद करने की बात कही। आरोप है कि इस पर दोनों युवक भड़क गए और गाली-गलौज करने लगे। शिकायत के मुताबिक, युवकों ने अपने पास रखा धारदार चाकू निकाल लिया और उसे लहराते हुए गार्ड को जान से मारने की धमकी दी।

घर में सुख, शांति के लिए रखें फेंगशुई से जुड़ी ये चीजें

जिस तरह से वास्तु शास्त्र में घर से जुड़ी हर वस्तु की सही दिशा, स्थान, उपाय आदि बताए गए हैं, ठीक इसी तरह फेंगशुई टिप्स भी हैं जिनका ख्याल रखने से घर में सुख-समृद्धि और शांति बनी रहती है। इसलिए फेंगशुई को चीन का वास्तु शास्त्र भी कहते हैं। फेंगशुई का शाब्दिक अर्थ है वायु और जल। घर का निर्माण किस प्रकार करें, कैसे घर को सुंदर बनाएं, घर में क्या-क्या सामान होना चाहिए? इन सभी बातों की जानकारी हमें फेंगशुई में आसानी से मिलती है। फेंगशुई मानता है कि घर में कुछ विशेष वस्तुओं को सही दिशा और स्थान पर रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। इसी कड़ी में हम आपको ऐसी 5 फेंगशुई चीजों के बारे में बता रहे हैं, जो आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि लाने में सहायक मानी जाती हैं।

तीन टांग वाला मेंढक

फेंगशुई में तीन टांगों वाला मेंढक बेहद शुभ और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। खासतौर पर मुंह में सिक्का दबाए हुए मेंढक को धन आकर्षित करने वाला माना जाता है। इसे घर के अंदर मुख्य द्वार के पास रखना लाभकारी होता है। ध्यान रखें कि इसे रसोई या बाथरूम में न रखें, क्योंकि ऐसा करना नकारात्मक प्रभाव ला सकता है।

फेंगशुई कछुआ

फेंगशुई के मुताबिक कछुआ दीर्घायु, स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि यह घर में चल रही बाधाओं को धीरे-धीरे दूर करता है। यदि आप आर्थिक परेशानियों या अनावश्यक खर्च से जूझ रहे हैं, तो धातु का कछुआ रखना शुभ माना जाता है। इसे पानी से भरे कांच के पात्र में रखकर उत्तर दिशा में स्थापित करें। ऐसा करने से धन से जुड़ी स्थिति बेहतर होती है और कार्यों में स्थिरता आती है।

ड्रैगन का जोड़ा

फेंगशुई में दो ड्रैगन का जोड़ा समृद्धि और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इनके पंजों में मौजूद मोती ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। ड्रैगन को फेंगशुई के चार दिव्य प्राणियों में शामिल किया गया है और यह साहस, पुरुषत्व व वीरता का प्रतिनिधित्व करता है। डबल ड्रैगन को घर की किसी भी दिशा में रखा जा सकता है, लेकिन पूर्व दिशा में रखना सबसे अधिक शुभ और लाभकारी माना जाता है।

चीनी सिक्के

फेंगशुई के चीनी सिक्के समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। घर के मुख्य दरवाजे के हैंडल पर सिक्के लटकाना फेंगशुई में धन, संपत्ति और सौभाग्य को आकर्षित करने का आसान उपाय माना जाता है। इसके लिए आप तीन पुराने चीनी सिक्कों को लाल धागे या रिबन में बांधकर दरवाजे के हैंडल पर टांग सकते हैं। ध्यान रखें कि सिक्के दरवाजे की अंदर की ओर लटकें, बाहर की तरफ नहीं। साथ ही, यह उपाय सिर्फ मुख्य द्वार पर ही करें, हर दरवाजे पर सिक्के लगाना सही नहीं माना जाता।

लॉफिंग बुद्धा

अगर आप आर्थिक सफलता पाना चाहते हैं, तो लॉफिंग बुद्धा घर में जरूर रखें। अपने लिविंग रूम में मुख्य द्वार से तिरछी तरफ एक हंसता हुआ लाफिंग बुद्धा रखें। ऐसा करने से आके जीवन में समृद्धि आने के योग बनेंगे। लाफिंग बुद्धा मुख्य द्वार के एकदम सामने न रखें। बुद्धा समृद्धि के देवता हैं। इनकी मुस्कान में ही समृद्धि है। इसके अलावा घर की दक्षिण-पूर्व दिशा में रखने से धन से जुड़ी एनर्जी एक्टिव होती है।

चेहरा धोते समय होने वाली गलतियों से बचे

त्वचा की देखभाल का पहला और सबसे जरूरी काम है चेहरे की सही तरीके से सफाई। दिनभर की धूल, पसीना और प्रदूषण त्वचा पर जमा होकर उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। लोग ये बात जानते हैं, इसलिए वह चेहरा धोना नहीं भूलते। लेकिन ज्यादातर लोग चेहरा धोते समय ही ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो धीरे धीरे उनकी त्वचा को रूखा, बेजान और संवेदनशील बना देती है। इसलिए केवल चेहरा धोना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सही तरीके से फेस वॉश करना जरूरी है। त्वचा विशेषज्ञों के अनुसार, अगर चेहरा धोने का तरीका सही न हो तो महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट भी अपना असर नहीं दिखा पाते। आइए जानते हैं चेहरा धोते समय होने वाली आम गलतियां और उनसे बचने का सही तरीका।

दिन में बार-बार चेहरा धोना

कई लोग दिनभर में 5-6 बार चेहरा धोते हैं, जिससे त्वचा को नुकसान हो सकता है। ऐसा करने से त्वचा का नैचुरल ऑयल खत्म हो जाता है। स्किन ज्यादा ऑयल बनाने लगती है और मुंहासे बढ़ सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार चेहरा धोना पर्याप्त होता है।

बहुत गर्म पानी से चेहरा धोना

कई लोग चेहरे की सफाई के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह आदत त्वचा के लिए नुकसानदेह हो सकती है। इससे त्वचा की प्राकृतिक नमी खत्म हो सकती है। गर्म पानी में मुंह धोने से स्किन ड्राई और संवेदनशील हो सकती है। साथ ही त्वचा की सुरक्षा परत कमजोर पड़ सकती है। सही तरीका है कि चेहरा धोने के लिए हमेशा हल्के गुनगुने या ठंडे पानी का इस्तेमाल करें।

जरूरत से ज्यादा फेस वॉश लगाना

कुछ लोगों को लगता है कि ज्यादा फेस वॉश लगाने से चेहरा ज्यादा साफ होगा, लेकिन यह सच नहीं है। ज्यादा फेश वॉश लगाने से त्वचा ज्यादा ड्राई हो सकती है। त्वचा का नैचुरल ऑयल खत्म हो जाता है और जलन या रेडनेस हो सकती है। चेहरा धोने के लिए मटर के दाने जितना फेस वॉश पर्याप्त होता है।

स्किन टाइप के अनुसार फेस वॉश न चुनना

हर त्वचा की जरूरत अलग होती है। गलत फेस वॉश इस्तेमाल करने से भी स्किन की समस्या बढ़ सकती है। जैसे ऑयली स्किन के लिए जेल बेस्ड फेस वॉश सही रहता है। ड्राई स्किन के लिए क्रीम बेस्ड फेस वॉश और सेंसिटिव स्किन के लिए माइल्ड क्लेंजर का उपयोग करना चाहिए। चेहरा धोने के बाद कई लोग वही तौलिया इस्तेमाल करते है जो पूरे शरीर के लिए इस्तेमाल होता है। इसके कारण बैक्टीरिया त्वचा पर फैल सकते हैं। मुंहासे और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। फेस वॉश के बाद चेहरे को पोछने के लिए अलग और साफ तौलिया इस्तेमाल करें।

हाथ में भी होती है झुनझुनी और सुन्नपन जानें किस वजह से

क्या आपके हाथों में बार-बार झुनझुनी या सुन्नपन महसूस होता है? कई लोग इसे मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह शरीर का एक संकेत भी हो सकता है, जिसे समझना जरूरी है। अक्सर यह समस्या तब महसूस होती है जब हम गलत पोजीशन में सो जाते हैं या लंबे समय तक एक ही स्थिति में हाथ रखते हैं। ऐसे में नसों पर दबाव पड़ता है या खून का प्रवाह कुछ समय के लिए कम हो जाता है, जिससे झुनझुनी होने लगती है।

कब होती है दिक्कत?

लेकिन अगर यह परेशानी बार-बार होने लगे या लंबे समय तक बनी रहे, तो इसके पीछे कोई खास कारण भी हो सकता है। theheartysoul की रिपोर्ट के अनुसार, सबसे आम वजहों में से एक है कार्पल टनल सिंड्रोम, जिसमें कलाई की नस दब जाती है और अंगूठे, उंगलियों में झुनझुनी या दर्द होने लगता है। कभी-कभी समस्या कलाई में नहीं, बल्कि कोहनी या गर्दन से भी जुड़ी हो सकती है। नसों में कहीं भी दबाव आने से हाथ तक इसका असर पहुंच सकता है, जिससे झुनझुनी और कमजोरी महसूस होती है।

ब्लड सर्कुलेशन और डायबिटीज भी कारण

खराब ब्लड सर्कुलेशन भी इसका एक कारण हो सकता है। ठंड में या अचानक तापमान बदलने पर उंगलियां सुन्न पड़ सकती है और रंग भी बदल सकता है, जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा, डायबिटीज जैसी बीमारियां भी नसों को प्रभावित कर सकती हैं। जब नसें कमजोर होने लगती हैं, तो हाथ-पैरों में झुनझुनी, जलन या सुन्नपन महसूस होने लगता है।

विटामिन B12 की कमी

विटामिन B12 की कमी भी एक अहम कारण है, जो धीरे-धीरे नसों को नुकसान पहुंचा सकती है. कई बार लोग थकान या कमजोरी को नजरअंदाज करते रहते हैं, लेकिन यह संकेत हो सकता है कि शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी है. कुछ मामलों में थायरॉयड की समस्या भी हाथों में झुनझुनी का कारण बन सकती है. शरीर का मेटाबॉलिज्म बिगड़ने से नसों पर असर पड़ता है और यह समस्या बढ़ सकती है.

प्रो शरीर के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी

प्रोटीन का काम मांसपेशियों को बनाना और उन्हें मजबूत बनाना होता है। कुछ लोगों का मानना है कि इसकी जरूरत सिर्फ जिम जाने वालों को होती है। जबकी ऐसा नहीं है, क्योंकि चलने-फिरने और शारीरिक ताकत के लिए भी प्रोटीन जरूरी है। हमारे शरीर में हर समय पुरानी कोशिकाएं मरती हैं और नई बनती हैं। घाव भरने, चोट ठीक करने और टिशू को फिर से बनने के लिए प्रोटीन की ही जरूरत होती है। वेजिटेरियन लोग अक्सर इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि प्रोटीन के लिए वह क्या खाएं। इंस्टाग्राम पर जनरल फिजिशन एंड डायबिटीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर कोमल कुलकर्णी ने इंडियन डायट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए क्या खाएं के बारे में बताया है।

1) दाल :- दाल 'सुपरफूड' की तरह काम करती है। डायट में प्रोटीन को शामिल करने के लिए मिक्स दाल खाएं। डॉक्टर कहती हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी रखें और इसमें पनीर को कद्दूकस करके शामिल करें।

2) दही :- दही सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। इंडियन खाने में इसे अमृत माना जाता है। डॉक्टर प्रोटीन के लिए हंग कर्ड खाने की सलाह देती हैं। दिनभर में दो कटोरी खा सकते हैं। चाहे तो इसे पोहा के साथ मिलाकर खा सकते हैं।

3) रोटी :- इंडियन थाली रोटी जरूर होती है। सिर्फ गेहूं के आचे की रोटी खाने से अच्छा है कि आप रोटी के आटे में बेसन या फिर सोया का आटा मिलाएं। इसके अलावा और आटे में मैश किया पनीर भी मिला सकते हैं।

4) स्नैक्स :- लंच के बाद शाम के समय हल्की भूख लगने लगती है। शाम के समय स्नैक्स में नमकीन -बिस्कुट को छोड़कर रोस्टेड चना और मूंगफली को शामिल करें।

5) चावल :- चावल कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है। हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ता है, जो शरीर को तुरंत काम करने की ताकत देता है। डॉक्टर प्लेन चावल की जगह खिचड़ी खाएं।

आज का राशिफल

मेष राशि - आपकी राशि के तृतीय भाव से चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। करियर में आपको अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। बिजनेस में नई योजनाएं फलित होंगी और आर्थिक लाभ के योग बनेंगे। लव लाइफ में साथी के साथ घरेलू बातों को लेकर थोड़े मतभेद हो सकते हैं, धैर्य से काम लें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और माता-पिता की सेहत का ख्याल रखें।

वृषभ राशि - बिजनेस में नए संपर्क बनेंगे जो भविष्य में लाभकारी सिद्ध होंगे। लव लाइफ में साथी के साथ संबंध और अधिक मधुर होंगे और आप एक-दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे। स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक रहेगा और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। कल का दिन नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा है। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, कल का दिन आपके लिए खुशियां लेकर आएगा।

मिथुन राशि - आपके नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा होगी। बिजनेस में लाभ के बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे। लव लाइफ में साथी के साथ रोमांटिक पल व्यतीत करेंगे। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और आप मन से भी काफी प्रसन्न रहेंगे। कल आपका आत्मविश्वास बहुत ऊंचा रहेगा। जो भी काम आप हाथ में लेंगे, उसे समय पर और बेहतर ढंग से पूरा करेंगे।

कर्क राशि - आपके पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। बिजनेस में नई योजनाएं सफल होंगी और व्यापारिक सौदों में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। लव लाइफ में साथी के साथ तालमेल बहुत ही सुंदर रहेगा और आपसी प्रेम गहरा होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन अच्छा है, ऊर्जा का स्तर ऊंचा बना रहेगा। कल कार्यक्षेत्र में आपकी पहचान एक कुशल रणनीतिकार के रूप में बनेगी।

सिंह राशि - चंद्रमा आपकी राशि के एकादश भाव से द्वादश भाव में प्रवेश करेगा। करियर में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे और आपके रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे। बिजनेस में कोई बड़ा सौदा फाइनल हो सकता है, जो भविष्य के लिए लाभकारी रहेगा। लव लाइफ में साथी के साथ आपका रिश्ता और भी गहरा होगा। स्वास्थ्य के प्रति आप पहले से बेहतर महसूस करेंगे, ऊर्जा का संचार बना रहेगा।

कन्या राशि - करियर में सहकर्मियों से सतर्क रहें और फालतू की बातों में समय न गंवाएं। बिजनेस में अभी किसी भी प्रकार के बड़े निवेश को टालना ही बेहतर होगा। लव लाइफ में साथी की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है, उनका ध्यान रखें। स्वास्थ्य में पेट या पाचन से जुड़ी समस्याओं के प्रति सचेत रहें और हल्का भोजन लें।

तुला राशि-साझेदारी वाले कार्यों से लाभ मिलने की संभावना है। बिजनेस में अपने प्रतिस्पर्धियों पर नजर रखें और योजनाबद्ध तरीके से काम करें। लव लाइफ में साथी के साथ रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी और आप दोनों एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य है, बस नियमित खान-पान का ध्यान रखें।

वृश्चिक राशि - पुरानी मेहनत का फल मिलेगा और आपके विरोधी शांत रहेंगे। बिजनेस में लाभ की अच्छी स्थिति बनी रहेगी। लव लाइफ में साथी के साथ मधुर संबंध रहेंगे और आप दोनों एक-दूसरे की बातों को बेहतर समझेंगे। स्वास्थ्य में सुधार आएगा और आप नई स्फूर्ति का अनुभव करेंगे।

धनु राशि- आपके रचनात्मक विचारों की प्रशंसा होगी और आप अपने काम में निखार ला पाएंगे। बिजनेस में कोई बड़ा लाभ मिल सकता है, बशर्ते आप सही योजना बनाएं। लव लाइफ में साथी के साथ हल्की-फुल्की नोकझोंक हो सकती है, लेकिन प्रेम बना रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मकर राशि - घर-परिवार की समस्याओं के कारण कार्यस्थल पर ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत आ सकती है। बिजनेस में सावधानी से काम लें और कोई बड़ा फैसला न लें। लव लाइफ में साथी के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ा धैर्य की जरूरत होगी। स्वास्थ्य में माता-पिता की सेहत का विशेष ध्यान रखें।

कुंभ राशि- आपके साहस और मेहनत की सराहना होगी, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा। बिजनेस में नए संपर्क बनेंगे जो भविष्य में लाभकारी सिद्ध होंगे। लव लाइफ में साथी के साथ रिश्ता और भी अधिक गहरा होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप पूरी तरह से ऊर्जावान महसूस करेंगे।

मीन राशि- धन संबंधी मामलों में बहुत सतर्क रहें और सोच-समझकर ही पैसा खर्च करें। बिजनेस में किसी को भी बिना जांच-परख के उधार न दें। लव लाइफ में वाणी पर संयम रखें, क्योंकि आपके गलत शब्द रिश्ते में खटास पैदा कर सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से गले या आंखों का थोड़ा ध्यान रखें।

शरीर को ठंडा और शांत रखने में मददगार टिप्स

गर्मियों के मौसम में अचानक पसीना, हॉट फ्लैशेज, एसिडिटी, खराब नींद, स्किन में समस्याएं जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। यहां शरीर को ठंडा रखने और शांत रखने में मदद करने वाले आयुर्वेदिक टिप्स के बारे में बता रहे हैं। कुछ शानदार आयुर्वेदिक टिप्स

गर्मियों में जब शरीर बहुत ज्यादा गर्म होता है तब आपको अचानक पसीना, हॉट फ्लैशेज, एसिडिटी, खराब नींद, स्किन में समस्याएं जैसे लक्षण दिख सकते हैं। आयुर्वेद में इसका मतलब पित्त इंबैलेंस होता है। यहां आयुर्वेदिक एक्सपर्ट दीक्षा भावसार द्वारा बताई सिंपल आयुर्वेदिक तरीकों के बारे में बता रहे हैं जो शरीर को नेचुरली ठंडा और शांत रखने में मदद करेंगी।

नारियल पानी

ये शरीर को नैचुरली ठंडा रखता है। इसे पीने पर इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस होते हैं और शरीर की अंदरूनी गर्मी कम होती है। एक गिलास फ्रेश नारियल पानी दोपहर या सुबह 10 से 12 बजे के बीच पिएं।

भिगी हुई किशमिश या मुनक्का

ये शरीर को नैचुरली ठंडा रखने और हार्मोन बैलेंस करने में मदद करती है। इसके अलावा ये शरीर की गर्मी कम करने में भी मददगार होता है। 8 से 10 काली किशमिश को रातभर भिगोएं और फिर सुबह किशमिश खाएं और पानी पिएं।

सबजा सीड्स

ये शरीर को तुरंत ठंडा करने, एसिडिटी कम करने और बॉडी टेम्प्रेचर को मेंटेन करने में मदद करता है। एक चम्मच सबजा सीड्स को 10 से 15 मिनट के लिए भिगोएं। फिर इन बीजों को नारियल पानी, नींबू पानी या छाछ में मिलाकर पिएं।

धनिया का पानी

ये लिवर डिटॉक्स करने और बॉडी हीट को कम करने में मदद करता है। ये हार्मोन बैलेंस करने में मदद करता है। इसके लिए एक चम्मच धनिया बीज को रातभर पानी में भिगोएं और फिर अगली सुबह पिएं।

सौंफ का पानी

सौंफ का पानी शरीर के अंदर की गर्मी को कम करने का काम करता है। इससे पाचन बेहतर रहता है और एसिड से जुड़ी हीट की समस्या कम होती है। इसके लिए सौंफ के बीज को पानी में रातभर के लिए भिगोएं और फिर अगली सुबह छानकर पिएं।

गाय का घी

नसों को शांत करने, बॉडी हीट को कम करने और स्लीप बेहतक करने के लिए गाय का घी बेस्ट है। रोजाना रात में सोने से पहले गुनगुने एटू गाए घी से पैर के तलवों की मालिश करें।

शीतकारी प्राणायाम

ये शरीर को तुरंत ठंडा करता है और स्ट्रेस के साथ शरीर की गर्मी को भी कम करता है। इसे रोजाना 5 मिनट करें।

बेहतरीन रेसिपी

करेले की कड़वाहट की वजह से बहुत से लोग इसे खाने से कतराते हैं, लेकिन अगर इसे सही तरीके से बनाया जाए, तो यह बेहद टेस्टी लगते हैं। बहुत से घरों में करेला भरवां तरीके से बनाया जाता है, लेकिन इसकी सूखी सब्जी भी स्वाद में जबरदस्त लगती हैं। हम आपके लिए सूखे करेले की सब्जी बनाने की एक बेहतरीन रेसिपी लेकर आए हैं।

सब्जी बनाने की सामग्री

आधा किलो करेला, आधा छोटा चम्मच बेसन, दो बड़े चम्मच सरसों का तेल, एक छोटा चम्मच जीरा, आधा चम्मच कलौंजी,एक चम्मच नमक, दो बड़े चम्मच नींबू का रस, दो चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, दो चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर हल्दी पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच सौंफ, एक चम्मच गरम मसाला, 7-8 मेथी दाना, एक चम्मच साबूत धनिया, दो चुटकी हींग, आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, कसूरी मेथी, कटा हुआ हरा धनिया सूखी सब्जी के स्वाद में जबरदस्त लगती हैं।

बनाने की विधि

करेले को पानी से धो लें और फिर गोल-गोल थोड़ी मोटी स्लाइस में काट लें। अब इन्हें एक कटोरे में रखें और ऊपर से नमक डालें। अच्छे से हाथों से मिक्स करें और फिर जब पानी निकलने लगे तो करेले को हाथों में लेकर अच्छे से निचोड़ लें और फिर एक तरफ रखें। अब अलग रखे करेले में लाल मिर्च पाउडर, भुना जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, बेसन और हल्दी पाउडर डालें। अच्छे से मिक्स करें और फिर इसमें थोड़ा सरसों का तेल डालकर कुछ देर के लिए रख दें। अब एक कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म करें और फिर जीरा, मेथी दाना, हींग, सौंफ, कलौंजी डालकर अच्छे से चटका लें। फिर मसाले के साथ मिक्स किए करेले को तेल में डालें और अच्छे से मिक्स कर लें। जब करेले अच्छे से पक जाएं तो इसमें नमक और अमचूर पाउडर और गरम मसाला पाउडर डालें। अंत में हरा धनिया डालें और सर्व करें।

पार्टी-फंक्शन के लिए करें साड़ियों का चुनाव

साड़ी का फैशन कभी पुराना नहीं होता, बस वक्त के साथ इसे पहनने के स्टाइल बदल जाते हैं। बनारसी, कांजीवरम और सिल्क जैसी साड़ियां आज भी सदाबहार हैं और महिलाओं की पहली पसंद बनी हुई हैं। अगर आप भी साड़ी लवर हैं और हर पार्टी-फंक्शन में साड़ी पहनना पसंद करती हैं, तो आपकी वॉर्डरोब में कुछ खास डिजाइन और पैटर्न वाली साड़ियां जरूर होनी चाहिए। इन खास साड़ियों को पहनकर न सिर्फ आपका लुक रॉयल लगेगा, बल्कि एक अलग ही एलिगेंस फील होगा। स्टाइलिश कोच आशी वर्मा ने ऐसी साड़ियों के बारे में बताया है, जो हर महिला की अलमारी में जरूर होनी चाहिए। उनका कहना है कि इन साड़ियों को कैरी करके आप किसी महारानी से कम नहीं लगेंगी और हर मौके पर सबसे अलग और खूबसूरत नजर आएंगी।

1- बनारसी सिल्क साड़ी

बनारसी साड़ी का पैटर्न कभी पुराना नहीं हुआ। गोल्डन बॉर्डर के साथ बनारसी साड़ी को हमेशा से रॉयल्टी और क्लास के लिए जाना जाता है। इसकी खासियत है इसका बारीक जरी वर्क और रिच सिल्क फैब्रिक जो हर खास मौके के लिए परफेक्ट होता है। बनारसी साड़ी का हैवी वर्क आपको रॉयल लुक देगा।

2- टिशू सिल्क साड़ी

आजकल बॉलीवुड एक्ट्रेस का फेवरेट रॉयल ट्रेंड बन चुकी है टिशू सिल्क साड़ी। इसका हल्का, शिमरी और ग्लॉसी टेक्सचर इसे बेहद एलिगेंट और लग्जरी लुक देता है। इसमें गोल्डन या सिल्वर शीन होती है जो लाइट में खूबसूरती से चमकती है, नाइट पार्टी के लिए ये परफेक्ट होती है।

3- कांजीवरम साड़ी

साउथ इंडियन रॉयल लुक के लिए कांजीवरम साड़ी सबसे बेस्ट रहेगी। कांजीवरम साड़ियां अपनी रिच सिल्क क्वालिटी और चौड़े गोल्ड बॉर्डर के लिए जानी जाती है। ये साड़ी सिर्फ साउथ ही नहीं बल्कि पूरे देश में रॉयल लुक के लिए जानी जाती है। मोटे सिल्क फैब्रिक और कॉन्ट्रास्ट बॉर्डर इसे बेहद ग्रेसफुल बनाते हैं। किसी खास मौके के लिए ये साड़ी बेस्ट रहेगी।

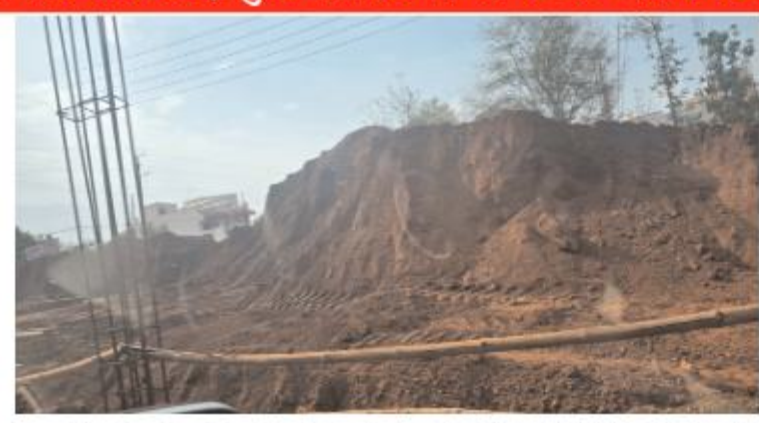

कोहका, में अवैध पेट्रोल पंप निर्माण के कारण खोदे गए गड्ढे को नगर निगम ने जेसीबी लगाकर समतल किया

नगर निगम कमिश्नर से भाजपा नेता शारदा गुप्ता ने शिकायत पर निगम कमिश्नर ने मुआयना कर कार्रवाई की

भिलाई। कुरूद रोड कोहका, भिलाई में अवैध रूप से पेट्रोल पंप द्वारा खोदे गए गड्ढे के कारण क्षेत्र की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए गया था। निर्माण के दौरान बिजली के पोल के बिल्कुल पास गड्ढा खोद दिया गया है, जिससे पोल की नींव कमजोर हो चुकी थी।

यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक थी, क्योंकि कभी भी बिजली का पोल गिर सकता था, जिससे राहगीरों और आसपास के निवासियों की जान को खतरा उत्पन्न हो गया था। साथ ही, इससे बड़े पैमाने पर बिजली आपूर्ति बाधित होने की आशंका भी बनी हुई थी। शिकायत के बाद प्रशासन तत्काल हरकत में आकर समस्त गड्ढे को समतल कर दिया गया है।

इसकी शिकायत कलेक्टर जनदर्शन पीएमओ कार्यालय तक की जा चुकी थी।

स्थानीय नागरिकों में इस लापरवाही को लेकर भारी आक्रोश व्याप्त था। लोगों का कहना है कि बिना किसी सुरक्षा मानकों का पालन किए इस प्रकार का निर्माण कार्य किया जाना सीधे तौर पर जन सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है।

भाजपा प्रदेश संवाद प्रमुख झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के संयोजक शारदा गुप्ता ने कहा कि क्षेत्र में किसी भी हाल में पेट्रोल पंप खोलने नहीं दिया जाएगा।

जिम्मेदार व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। नगर निगम के क्षेत्रीय पार्षद अभिषेक मिश्रा ने पूरे समय खड़े रहकर गड्ढे को लेवलिंग कराया उन्होंने भी उन्होंने क्षेत्र के लोगों को आश्वासन दिया कि किसी भी हाल में पेट्रोल पंप नहीं खुलने दिया जाएगा।

शारदा गुप्ता ने प्रशासन से अपील है कि इस गंभीर मामले को संज्ञान में लेते हुए शीघ्र आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि किसी संभावित दुर्घटना को रोका जा सके। मांग करने वाले में प्रमुख रूप से जे आनंद बसंत भारती प्रशांत पासवान सुगंधी वर्मा निर्मल भारती संतोष सोनी टाटा शोभा रेखा ब्रंहे मनीष यश दुलानी योगेश यदु संजय शर्मा निशु पांडे श्याम रविसिंग विनोद उपाध्याय कन्हैया सोनी बृजमोहन उपाध्याय विरेन्द्र यादव विनोद मून विशालदीप नायर अनिल सिंह सुभाष शर्मा मदन सेन पारस जंघेल नितेश मिश्रा विजय साहू राजेश सिंह सुनील मौर्य बंटी नाहर जेपी घनघोरकर संगम अग्रवाल संतोष जयसवाल गुरनाम सिंह भास्कर राव अखिलेश वर्मा महेश वर्मा राजेश प्रधान गौरी चक्रवर्ती भास्कर तिवारी राजू रमेश देशमुख नेहरू साहू अशोक द्विवेदी हरीशचंद्र भारती टिंकू संजय दुबे, गिरीश खापर्डे दिलीप दामले, नरेश मूकेश अजय प्रसाद नंदलाल प्रसाद अफजल अहमद प्रदीप पांडे सचिन गुप्ता ओपी गुप्ता विमलेश पांडे ओमप्रकाश यादव सहित प्रमुख कार्यकर्ताओं ने मांग की है।

बिजली दर वृद्धि पर कांग्रेस का हल्लाबोल, बिजली कार्यालय घेराव कर फूंका मुख्यमंत्री

कवर्धा। बिजली दरों में लगातार बढ़ोतरी, बढ़ती महंगाई, किसानों की समस्याओं और भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी कबीरधाम ने बुधवार को जोरदार प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष नवीन जायसवाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली कार्यालय का घेराव कर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

प्रदर्शन से पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी की विस्तृत बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और सरकार की नीतियों के खिलाफ जनजागरण अभियान तेज करने पर चर्चा हुई। बैठक में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि जनता से जुड़े मुद्दों पर संघर्ष को गांव-गांव, वार्ड-वार्ड और बूथ-बूथ तक पहुंचाया जाएगा। जिलाध्यक्ष नवीन जायसवाल ने कहा कि भाजपा सरकार लगातार जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ा रही है। एक ओर आम लोग महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकट से जूझ रहे है, वहीं दूसरी ओर बिजली दरों में वृद्धि कर उनकी मुश्किलें और बढ़ाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं, किसानों और छोटे व्यापारियों पर थोपा गया यह फैसला कांग्रेस किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी। पूर्व प्रदेश महामंत्री अर्जुन तिवारी ने कहा कि भाजपा की गलत नीतियों के कारण बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं भी आम लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। पूर्व विधायक ममता चंद्राकर ने सरकार पर युवाओं की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि रोजगार के अवसर लगातार घट रहे हैं और महंगाई चरम पर है।पूर्व जिला अध्यक्ष नीलकंठ चंद्रवंशी ने कहा कि खेती-किसानी के महत्वपूर्ण समय में किसानों को खाद, बीज और सिंचाई संसाधनों के लिए भटकना पड़ रहा है। वहीं होरीराम साहू ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार केवल घोषणाओं की राजनीति कर रही है, जबकि जमीनी हकीकत पूरी तरह अलग है। कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया कि बिजली दर वृद्धि, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर पार्टी का आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। कार्यक्रम में ब्लॉक अध्यक्षों, प्रदेश पदाधिकारियों, वरिष्ठ नेताओं और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही।

उमा बाई और उनके परिवार के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना किसी वरदान से

बल्लीराजहरा। डौण्डीलोहारा विकासखंड के ग्राम रेंगनी निवासी उमा बाई और उनके परिवार के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना किसी वरदान से कम नहीं रही। कभी उनका परिवार कच्चे मकान में रहने को मजबूर था, जहां बरसात के दिनों में छत से लगातार पानी टपकता रहता था। बारिश के चार महीने पूरा परिवार डर और परेशानी के बीच जीवन बिताता था। रातों की नींद और दिन का सुकून दोनों छिन जाता था। बरसात शुरू होने से पहले हर साल खपरैल और दीवारों की मरम्मत करानी पड़ती थी, जिससे आर्थिक बोझ भी बढ़ता था। परिवार का सपना था कि उनका भी एक पक्का मकान हो, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण यह सपना पूरा होना मुश्किल लग रहा था। ऐसे समय में प्रधानमंत्री आवास योजना उनके लिए उम्मीद की किरण बनकर आई। वर्ष 2024-25 में उनका आवास स्वीकृत हुआ और मकान निर्माण के लिए 1 लाख 20 हजार रुपये की राशि मिली। इसके बाद धीरे-धीरे उनका पक्का मकान तैयार हो गया। अब परिवार सुरक्षित और निश्चिंत होकर अपने नए घर में रह रहा है। उमा बाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की इस योजना ने उनके परिवार का वर्षों पुराना सपना पूरा कर दिया। अब उन्हें बारिश के मौसम का डर नहीं सताता और पूरा परिवार खुशहाल जीवन जी रहा है।

घर-घर पहुंचेगा योग, स्वस्थ होगा कबीरधाम: योग दिवस को लेकर व्यापक

कवर्धा। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को लेकर कबीरधाम जिले में तैयारियां अब जोर पकड़ चुकी हैं। 21 जून को होने वाले योग दिवस को इस बार व्यापक स्तर पर सफल बनाने के लिए जिला स्तर पर विशेष रणनीति तैयार की गई है। केवल औपचारिक आयोजन तक सीमित रहने के बजाय इस बार योग को जन-जन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। जिले के चारों ब्लॉकों सहित अनेक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में योग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पतंजलि योग समिति के अध्यक्ष सुरेश चंद्रवंशी ने बताया कि इस वर्ष योग दिवस को लेकर जिलेभर में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। समिति द्वारा लगातार लोगों को योग से जोड़ने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि तन, मन और आत्मा को संतुलित करने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने यह भी बताया कि नगर के सिग्नल चौक स्थित शारदा संगीत महाविद्यालय में प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 7 बजे तक योग दिवस की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। यहां नियमित रूप से योगाभ्यास, प्राणायाम और सामूहिक प्रशिक्षण कराया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में नगरवासी भाग ले रहे हैं। जानकारी के अनुसार कवर्धा जिले के चार प्रमुख ब्लॉकों–कवर्धा, पंडरिया, बोड़ला और सहसपुर लोहारा–में योग गतिविधियों को तेज कर दिया गया है। प्रशासनिक स्तर से लेकर सामाजिक संगठनों और योग समितियों तक सभी इस अभियान को सफल बनाने में जुटे हैं। लक्ष्य स्पष्ट है–हर व्यक्ति तक योग का संदेश पहुंचे और स्वस्थ जीवनशैली को अपनाने की प्रेरणा मिले। योग को केवल एक दिन के आयोजन तक सीमित न रखते हुए इसे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने पर जोर दिया जा रहा है। जिले के विभिन्न स्थानों, सार्वजनिक स्थलों, संस्थानों और विशेष रूप से स्कूलों में योग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए प्रशिक्षित टीमों का गठन किया गया है, जो सीधे लोगों तक पहुंचकर योग की उपयोगिता और अभ्यास की विधियां बताएंगी। विशेष बात यह है कि पूरे जिले में अलग-अलग स्थानों पर दो-दो सदस्यों की टीम बनाई गई है। ये टीमें स्कूलों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जाकर योगाभ्यास कराएंगी। विद्यार्थियों, शिक्षकों और आम नागरिकों को योग के लाभों से अवगत कराया जाएगा। इससे नई पीढ़ी में योग के प्रति रुचि बढ़ने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में योग की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। बढ़ता तनाव, अनियमित खानपान, मोबाइल और स्क्रीन पर अत्यधिक निर्भरता तथा शारीरिक निष्क्रियता के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे समय में योग एक प्रभावी समाधान बनकर सामने आया है। यह केवल शरीर को लचीला और मजबूत नहीं बनाता, बल्कि मानसिक शांति, एकाग्रता और आत्मनियंत्रण भी बढ़ाता है।

विधायक दीपेश साहू के प्रयासों से बेमेतरा को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मिली बड़ी

शासकीय पं. जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय में शुरू होगा बैचलर ऑफ लॉ पाठ्यक्रम

बेमेतरा। बेमेतरा जिले के युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। बेमेतरा विधायक दीपेश साहू के अथक प्रयासों और निरंतर पहल से शासकीय पं.जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बेमेतरा में बैचलर ऑफ लॉ (एल.एल.बी.) पाठ्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। लंबे समय से जिलेवासियों एवं विद्यार्थियों द्वारा की जा रही कानून की पढ़ाई की मांग अब पूरी होने जा रही है। यह सौगात बेमेतरा जिले के शैक्षणिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए विधायक दीपेश साहू ने प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, उपमुख्यमंत्री अरुण साव एवं विजय शर्मा, कैबिनेट मंत्री टंक राम वर्मा सहित राज्य सरकार के प्रति हृदय से आभार एवं धन्यवाद व्यक्त किया है। विधायक दीपेश साहू ने कहा कि बेमेतरा जिले के लिए यह अत्यंत गर्व और खुशी का क्षण है। लंबे समय से जिले के विद्यार्थियों एवं युवाओं की मांग थी कि उन्हें कानून की पढ़ाई की सुविधा अपने ही जिले में मिले, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने सपनों को पूरा कर सकें। आज यह मांग पूरी होने जा रही है, जो पूरे बेमेतरा जिले के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि शासकीय पं.जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एल.एल.बी. पाठ्यक्रम प्रारंभ होना केवल एक शैक्षणिक सुविधा नहीं, बल्कि बेमेतरा के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। अब हमारे जिले के विद्यार्थी कानून की पढ़ाई के लिए दूर-दराज के शहरों में जाने से बचेंगे और उन्हें अपने क्षेत्र में ही बेहतर शिक्षा का अवसर मिलेगा। विधायक साहू ने कहा कि कानून की शिक्षा युवाओं को समाज में न्याय और अधिकारों के प्रति जागरूक बनाती है। एल.एल.बी. करने के बाद विद्यार्थी अधिवक्ता, न्यायिक सेवा, प्रशासनिक क्षेत्र, विधि सलाहकार सहित अनेक क्षेत्रों में अपना भविष्य बना सकते हैं। इससे जिले में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और युवाओं के लिए रोजगार एवं आत्मनिर्भरता के नए रास्ते खुलेंगे। उन्होंने कहा कि बेमेतरा जिले के विकास के लिए शिक्षा को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता है। जब किसी क्षेत्र में उच्च शिक्षा के नए अवसर आते हैं, तो उसका सकारात्मक प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। यह सौगात आने वाले समय में बेमेतरा को शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान दिलाएगी। विधायक साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार जनहित और विकास के कार्यों को गति दे रही है। शिक्षा के क्षेत्र में लिए जा रहे निर्णय युवाओं के भविष्य को मजबूत बनाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर प्रयास जारी रहेंगे, ताकि क्षेत्र का प्रत्येक युवा आगे बढ़ सके और बेमेतरा विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके।

निर्माण कार्यों की गुणवत्ता मानक अनुरूप

कवर्धा। नगर पंचायत पांडातराई के सीएमओ श्री अभिषेक सिंह ने बताया कि नगर पंचायत क्षेत्रांतर्गत संचालित निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के संबंध में प्राप्त जानकारी एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक जांच एवं निरीक्षण के निर्देश दिए गए थे। सीएमओ ने बताया कि निकाय के उप अभियंता द्वारा मंगलवार को विभिन्न निर्माण कार्यों का स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण उपरांत उप अभियंता ने जानकारी दी कि वर्तमान में संचालित सभी निर्माण कार्य निर्धारित तकनीकी मानकों एवं स्वीकृत गुणवत्ता के अनुरूप किए जा रहे हैं तथा कार्यों की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी नहीं पाई गई है।

राजहरा में 5 दिवसीय बैडमिंटन टूर्नामेंट संपन्न, 70 खिलाड़ियों ने

दल्ली राजहरा। राजहरा बैडमिंटन एसोसिएशन के तत्वाधान में पांच दिवसीय रैंकिंग टूर्नामेंट 2026 का आयोजन स्थानीय बीएसपी राजहरा क्लब में हुआ। ग्रीष्मकालीन अवकाश में आयोजित इस टूर्नामेंट में जिले के विभिन्न स्कूलों से 70 से अधिक प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाया। खिलाड़ियों को तीन आयु वर्ग में बांटा गया था। सब जूनियर वर्ग में कक्षा 1 से 5वीं, जूनियर वर्ग में कक्षा 6वीं से 8वीं और सीनियर वर्ग में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के खिलाड़ी शामिल हुए। परिणाम में सब जूनियर वर्ग में रेयांश तिवारी प्रथम, आदित्य शर्मा द्वितीय और प्रेरणा मंडाले तृतीय स्थान पर रहे। जूनियर वर्ग में कुमार अदवित ने प्रथम, अभिज्ञान बास्के ने द्वितीय और नैतिक जैन ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं सीनियर वर्ग में सोहम कुकरेजा प्रथम, नमन कराडे द्वितीय एवं मित तलरेजा तृतीय स्थान पर रहे। राजहरा क्लब के बैडमिंटन प्रशिक्षक अमित बादल तिवारी ने बताया कि यह टूर्नामेंट पिछले 10 वर्षों से उनके और संपत राव मंडाले के सहयोग से लगातार आयोजित किया जा रहा है। इस बार भी 70 से अधिक बच्चों की भागीदारी ने आयोजन को सफल बनाया। बच्चों के पुरुस्कार वितरण में प्रमुख रूप से उपस्थित खदान मजदूर संघ भिलाई संबंद्ध भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष मुश्ताक अहमद अंसारी और भारतीय जनता पार्टी राजहरा मंडल अध्यक्ष रामेश्वर साहू ने विजेता खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका उत्साह वर्धन किया और विजेता खिलाड़ियों के साथ-साथ सभी खिलाड़ियों को सांत्वना पुरस्कार के रूप में स्मृति चिन्ह भेंट किया। उपस्थित सभी खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए खदान मजदूर संघ संबंद्ध भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष मुश्ताक अहमद ने कहा कि राजहरा बैडमिंटन ऐसोशियेशन के तत्वाधान में संपन्न हुई। प्रतियोगिता में जितने भी खिलाड़ियों ने भाग लिया है सभी को बहुत बहुत बधाई और जिस तरह राजहरा बैडमिंटन ऐसोशियेशन ने ग्रीष्मकालीन अवकाश का सदुपयोग कर बच्चों को एक अच्छा मंच उपलब्ध कराया और जिस एकाग्रता और जिम्मेदारी के साथ बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया वह काबिले तारीफ है, वही आपकी सफलता की कुंजी है। खेल शरीर में स्फूर्ति लाता है और मन को एकाग्र करता है, जो पढ़ाई के लिए भी उतना ही जरूरी है। जिस तरह से आप लोगों आज राजहरा बैडमिंटन ऐसोशियेशन का नाम पूरे बालोद जिले में रौशन किया है। अपने कोच बादल तिवारी का नाम रौशन किया है।

भाजपा अघोषित रूप से लोगों के घरों में डाका डालने का काम कर रही :

बेमेतरा। बेमेतरा जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने भाजपा की राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में घरेलू बिजली की दरों में 50 पैसे तक प्रति यूनिट बढ़ोतरी किए जाने को अघोषित रूप से सरकार के द्वारा आम जनता के घरों में डाका डालने की कार्यवाही कहां है पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा ने कहा कि भाजपा की चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार दोनों ही सरकारी अपनी-अपनी जगह पूरी तरह से विफल हो चुकी है डबल इंजन का जो कॉन्सेप्ट इन्होंने आम जनता के सामने रखा था वह पूरी तरह से फेल हो चुका है भाजपा सरकार अपने दिखावे एवं गुणगान करने के फेर में आम जनता का खूनचूसने का काम कर रही है पहले ही डीजल गैस के दामों में प्रतिमा 2 से 3 बार की जा रही बढ़ोतरी से आम आदमी की कमर टूटी हुई है, उस पर से बिजली बिल में बढ़ोतरी किया जाना वह भी तब जब राज्य सरकार आम जनता को बराबर विद्युत सप्लाई भी नहीं दे पा रही है दिन में प्रतिदिन 4 से 5 घंटे विद्युत कटौती भीषण गर्मी में लोगों को झेलनी पड़ रही है लोगों के घरों में लगातार बिजली कटौती के कारण विद्युत उपकरण खराब हो रहे हैं और उसे बनवाने का भार भी आम जनता को झेलना पड़ रहा है और बिजली बिल आसमान छू रहे हैं एक एक और जहां विद्युत मंडल ने लोगों से स्मार्ट मीटर के नाम पर बिजली बिल की लूट मचा रखी है। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार द्वारा लगातार विद्युत की दरो में बढ़ोतरी किया जाना फिर से लोगों को लालटेन युग में ले जाने की तैयारी लग रहा है। जिस तरह भाजपा सरकार चारों दिशाओं में फेल हो चुकी है, इनसे राज्य संभाल नहीं रहा है, मुख्यमंत्री बने रहने के लिए पार्टी कार्यालय को मोटी रकम भेजने के नाम पर, लोगों को परेशान किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी बेमेतरा द्वारा बिजली बढ़ोतरी को लेकर विद्युत मंडल कार्यालय का घेराव तथा मुख्यमंत्री का पुतला धन का कार्यक्रम रखा गया है। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ने आम जनता से भी इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक सहभागिता के अपील की है। साथ ही साथ जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से गुरूवार को, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर विद्युत बढ़ोतरी के संबंध में बात रखी जाएगी।

स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय में न्योता भोजन के साथ मनाया गया शाला

बेमेतरा। नवीन शैक्षणिक सत्र के शुभारंभ अवसर पर स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय में शाला प्रवेश उत्सव एवं न्योता भोजन कार्यक्रम का उत्साहपूर्ण आयोजन किया गया। राज्य शासन द्वारा संचालित शाला प्रवेश उत्सव का मुख्य उद्देश्य शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करना, बच्चों को विद्यालय से जोड़ना तथा नवप्रवेशी विद्यार्थियों का स्वागत करना है। कार्यक्रम का शुभारंभ शाला प्रबंधन एवं विकास समिति की अध्यक्ष प्रेमलता नेमा, सहायक संचालक एस.पी. कोसले, एपीसी खेमराज साहू, संस्था की प्राचार्य कविता बाजपेई, प्रधान पाठक रामेश्वर प्रसाद बंजारे तथा उपस्थित पालकों द्वारा किया गया। अपने उदबोधन में प्राचार्य कविता बाजपेई ने नवप्रवेशी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने विद्यार्थियों को नियमित रूप से विद्यालय आने एवं मन लगाकर अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया तथा पालकों से भी बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया। शाला प्रबंधन समिति की अध्यक्ष प्रेमलता नेमा ने विद्यार्थियों को लगन एवं परिश्रम के साथ अध्ययन करने हेतु प्रेरित किया। जिला भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष प्रज्ञा निर्वाणी ने बच्चों को प्रेरक उदाहरणों के माध्यम से समझाया कि जिस प्रकार बूंद-बूंद से घड़ा भरता है और प्रतिदिन थोड़ी-थोड़ी बचत से बड़ी राशि एकत्रित हो जाती है, उसी प्रकार प्रतिदिन नियमित अध्ययन से परीक्षा में सफलता प्राप्त होती है। उनके प्रेरणादायी विचारों से विद्यार्थियों में विशेष उत्साह का संचार हुआ। इस अवसर पर कक्षा छठवीं के नवप्रवेशी विद्यार्थियों का गुलाल तिलक लगाकर स्वागत किया गया तथा उन्हें पाठ्यपुस्तकों एवं गणवेश का वितरण किया गया। साथ ही शैक्षणिक सत्र 2025-26 की वार्षिक परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कक्षा आठवीं केंद्रीकृत परीक्षा 2026 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली तृप्ति साहू, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली याचना वर्मा एवं गरिमा मांडवी तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली विधि पांडे को प्रमाण-पत्र एवं पेन प्रदान कर सम्मानित किया गया। शाला प्रवेश उत्सव के उपलक्ष्य में प्राचार्य कविता बाजपेई द्वारा विद्यार्थियों एवं अतिथियों के लिए न्योता भोजन का आयोजन भी कराया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिवार की ओर से प्रधान पाठक रामेश्वर प्रसाद बंजारे ने प्राचार्य को स्मृति भेंट प्रदान कर उनके योगदान के प्रति आभार व्यक्त किया।इसी दौरान नव न्युक्त जिला शिक्षा अधिकारी अभय जायसवाल एवं पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी आर चतुर्वेदी का आगमन हुआ। उनके द्वारा हलुवा टेस्ट किया गया और विद्यालय की गतिविधियों की जानकारी लिया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं लक्ष्मी पांडे, देवकी साहू, चेतन कुमार देवांगन, रेणुका अग्रवाल, संतोष कुमार यादव, रोहिणी साहू, सुनीता बंजारे एवं लक्ष्मीनि साहू सहित बड़ी संख्या में पालक एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।

समन्वय समिति की हुई बैठक

दल्लीराजहरा। छत्तीसगढ़ समन्वय समिति की एक बैठक समिति कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में समिति के पदाधिकारी, महिला प्रकोष्ठ, युवा प्रकोष्ठ एवं सभी छत्तीसगढ़िया समाजो के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव सहित प्रमुख सदस्य उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए रामदास मानिकपुरी ने कहा कि गर्मी के कारण बैठक में विलंब हुआ। अब संगठन को मजबूत करने के लिए प्रत्येक छत्तीसगढ़िया समाज में बैठक कर छत्तीसगढ़ की रीति-नीति, रहन-सहन और संस्कृति पर चर्चा की जाएगी। बैठक में शहर में रोजगार के अवसर बढ़ाने पर गंभीर मंथन हुआ। समाज प्रमुखों ने तय किया कि राजहरा में 6 मिलियन क्षमता का प्लांट खोलने के लिए बीएसपी के मुख्य महाप्रबंधक को शीघ्र ज्ञापन सौंपा जाएगा। बैठक में सामाजिक भवनों के विस्तार और भवन निर्माण पर भी चर्चा हुई। महासचिव तोरण लाल साहू ने बताया कि सभी के सहयोग से नगर पालिका में भाजपा सरकार बनी है। नगर पालिका की ओर से समिति के लिए लंबे समय से बाथरूम निर्माण की मांग थी, जिसके लिए 3.30 लाख की राशि प्रस्तावित की गई है। निर्माण कार्य जल्द पूर्ण होगा। आय-व्यय पर भी चर्चा की गई। बैठक में चेतन लाल साहू, घनश्याम पारकर, छब्बू लाल सेन, संतराम सेन, प्रेमलाल निर्मलकर, विद्या रावटे, पुष्पा शांडिल्य, ममता घराना, विनोद आरदे, महेश सहारे, मोरेलाल मिश्रा, प्रदीप, शीतल साहू, काशीराम निषाद, कमल किशोर, साधुराम, सुरेंद्र, डी.आर. रावटे, विष्णु चंद्रवंशी, ओमप्रकाश, योगेश यादव सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित थे।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक संजय तिवारी द्वारा असमा पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्रास मेमोरियल सेंटर के बाजू, जयस्तंभ चौक, रायपुर (छ.ग.)-492001 से मुद्रित करवाकर व गदा चौक, फरीद नगर रोड स्वर्गीय तुलाराम मेमोरियल स्कूल के पास सुपेला भिलाई, जिला- दुर्ग (छ.ग.) पिन कोड-490023 से प्रकाशित। संपादक : संजय तिवारी, मो. 9200000214 (समाचार चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार), समस्त विवादों का निपटारा न्यायलीन क्षेत्र दुर्ग होगा। डाक पंजीयन क्रमांक- सीजी/दुर्ग/लोकतंत्र प्रहरी/2026-28, Email : loktantraprahrinews@gmail.com